www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 24 जून, 2024

दैनिक जागरण

धैर्य की नैया से कठिन स्थितियों में भी बेड़ा पार लग जाता है

नई उम्मीदों का सत्र

नई लोकसभा के पहले सत्र को लेकर उत्सुकता पक्ष-विपक्ष के नवनिर्वाचित सांसदों को ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी होगी। इसलिए होगी, क्योंकि यह लोकसभा पिछली लोकसभा से भिन्न होगी। इस बार विपक्ष का संख्या बल कहीं अधिक है और सत्तापक्ष गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहा है। यद्यपि यह गठबंधन सरकार अतीत की गठबंधन सरकारों से भिन्न है, क्योंकि उसका नेतृत्व करने वाला दल यानी भाजपा बहुमत से कुछ ही पीछे है। इसके बावजूद संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। इस टकराव के आसार भी उभर आए हैं, क्योंकि विपक्ष को प्रोटेम स्पीकर के नाम पर आपत्ति है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के सहयोगियों के रूप में विपक्ष के वरिष्ठ सांसदों के नाम तय किए गए हैं, लेकिन कुछ विपक्षी दल ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वे इस आधार पर प्रोटेम स्पीकर का असहयोग कर सकते हैं कि इस पद के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन क्यों नहीं किया गया। वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाए, लेकिन परंपरा यही रही है। अच्छा होता कि इसी परंपरा का पालन किया जाता। जो भी हो, यह कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर पक्ष और विपक्ष में तकरार हो। प्रोटेम स्पीकर चंद दिनों के लिए बनाई गई अस्थायी व्यवस्था ही है।

बेहतर संख्या बल के चलते विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है और उसके नेताओं की ओर से विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में भी कुछ अनुचित नहीं, लेकिन इस तैयारी के नाम पर संसद में हंगामा और शोरशराबा करके ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा की जानी चाहिए जिससे संसद चलने ही न पाए। एक लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही के नाम पर विपक्ष संसद में हंगामा और अव्यवस्था पैदा करना उचित समझता है। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे कुल मिलाकर संसद की गरिमा ही गिरती है। जहां विपक्ष का यह दायित्व है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब करे वहीं सत्तापक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहे। यदि ऐसा नहीं होता तो यह निराशाजनक ही होगा। संसद की सार्थकता केवल इसमें नहीं है कि वहां विभिन्न मुद्दे उठाए जाएं, बल्कि इसमें है कि उन पर धीर-गंभीर तरीके से चर्चा हो। दुर्भाग्य से संसद में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ऐसी कोई चर्चा कठिनाई से ही होती है जिससे देश को कोई दिशा मिल सके और समस्याओं के समाधान की राह खोजी जा सके। उचित यह होगा कि दोनों ही पक्ष संसदीय कार्यवाही के जरिये एक उदाहरण पेश करें।

सरल हो प्रक्रिया

झारखंड में उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन लेनेवाले विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण का लाभ देने को लेकर पोर्टल का विमोचन किया जाना अच्छी पहल है। निश्चित रूप से इससे विद्यार्थी कहीं से भी आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मैनुअल आवेदन की जटिल प्रक्रियाओं से उन्हें मुक्ति मिलेगी। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ विद्यार्थियों को तभी मिल पाएगा, जब इसके लिए आवेदन देने से लेकर बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण देने तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया सरल हो। अच्छी बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस आवश्यकता को समझते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और संबंधित बैंकों के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा भी है कि गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ पूरी सुलभता के साथ मिले। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण महज चार प्रतिशत ब्याज की दर पर चयनित बैंकों से मिलेगा। इस योजना का लाभ लेकर वैसे मेधावी विद्यार्थी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन या अन्य डिग्रियां प्राप्त कर सकेंगे जो पैसे के अभाव में इससे वंचित रह सकते थे। अब आवश्यकता है इस योजना को मूर्त रूप देने की। निश्चित रूप से इसमें न केवल राज्य सरकार, बल्कि संबंधित बैंकों और शिक्षण संस्थानों को भी अपनी-अपनी भूमिका सही ढंग से निभानी होगी। कागजी प्रक्रियाओं में शिक्षा ऋण प्राप्त करने में देरी न हो तथा इसमें किसी तरह बैचौलिए न पनपें, इसपर भी ध्यान देना होगा। विद्यार्थी राज्य में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसपर भी राज्य सरकार को ध्यान देना होगा।

गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ विद्यार्थियों को तभी मिलेगा, जब इसके लिए आवेदन, बैंकों की ऋण देने और भुगतान की प्रक्रिया सरल हो

जीएसटी के दायरे में आएं पेट्रोलियम उत्पाद

विवेक देवराय

इस परिवर्तन की राह में कुछ तात्कालिक चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन इसके बड़े दूरगामी लाभ होंगे। लोगों को सस्ते पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता के साथ ही राजस्व व्यवस्था भी बेहतर होगी

आदित्य सिन्हा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू हुए सप्ताह भर बाद पूरे सात साल हो जाएंगे। एक लंबी कशमकश के बाद ही इस कर व्यवस्था ने आकार लिया था। जीएसटी जैसी व्यवस्था का सुझाव पहली बार वर्ष 2000 में विजय केलकर टास्क फोर्स की अनुशंसा के बाद सामने आया था, लेकिन चूंकि यह एक अत्यंत जटिल मुद्दा था तो इस पर व्यापक सहमति बनाना टेढ़ी खीर साबित हुआ। इसी कारण जीएसटी को साकार रूप लेने में लगभग सत्रह वर्ष लग गए। अपने पहले कार्यकाल में इस पर राजनीतिक सहमति बनाना मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही। इसने कई प्रकार के केंद्रीय एवं राज्यों के करों को एकीकृत करके टैक्स व्यवस्था को सुगम एवं सहज बनाने का काम किया। अभी जीएसटी की 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत दरों की चार श्रेणियां हैं। कुछ आवश्यक वस्तुएं इसके दायरे से मुक्त हैं। इस एकीकृत कर व्यवस्था ने कई पड़ावों पर लगने वाले विभिन्न करों की जगह एकबारगी कर भुगतान को सुनिश्चित किया। इससे समग्र कर बोझ घटने के साथ ही आर्थिक सक्षमता बढ़ी है। इसके माध्यम से कर संग्रह भी निरंतर बढ़ रहा है। इस साल मई में 1.73 लाख करोड़ रुपये जीएसटी के जरिये प्राप्त हुए। यह राशि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक रही। चूंकि जीएसटी के मूल स्वरूप में कई प्रविधानों को इसके आरंभ में शामिल नहीं किया गया था तो इस कर व्यवस्था में सुधारों की भी रह-रहकर चर्चा जोर पकड़ती रहती है। इसी सिलसिले में जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर चर्चा की। जिस समय जीएसटी लागू हुआ था तब वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने भी ऐसे प्रस्ताव की वकालत की थी। अब इस मुद्दे ने नए सिरे से जोर पकड़ा है। जीएसटी के व्यापक स्वरूप को देखा जाए तो ऐसी कोई भी पहल बहुत सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होगी।

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लेने के मुद्दे पर राज्यों ने आरंभ से ही हिचक दिखाई है। इसकी वजह भी बहुत सीधी है कि उन्हें इन उत्पादों से भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। अलग-अलग राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी सहूलियत के हिसाब से वैट लगाया है। वहीं केंद्र सरकार प्रति लीटर के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाती है, जिसकी दरें पूरे देश के लिए एकसमान होती हैं। केंद्र और राज्यों के सम्मिलित करों-ड्यूटी से उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमत बहुत ऊंची हो जाती है। यदि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में आएं तो आवश्यक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के चलते देश भर में एकसमान कीमतें संभव हो सकती हैं। इससे जिन राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम हैं, वहां उनमें बढ़ोतरी की आशंका होगी, जिसके अपने राजनीतिक जोखिम होंगे। साथ ही साथ जिन राज्यों में कीमत अत्यधिक ऊंची है, वहां दाम गिर जाएंगे।

पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति शृंखला को भी बेहतर बनाएंगी एकसमान दरें ● फाइल

यदि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी का हिस्सा बनाया जाए तो इसके कई फायदे देखने को मिलेंगे। इससे जहां आर्थिक सक्षमता बढ़ेगी, वहीं उपभोक्ताओं का भी भला होगा। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और राज्यों के स्तर पर बहुस्तरीय कर व्यवस्था लागू है। इससे कीमतों का एक जटिल एवं मनमाना ढांचा बन गया है। इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से देश भर में मानक दरें लागू होंगी और कीमतों के स्तर पर विसंगतियां समाप्त होंगी। जीएसटी में आने से करों का स्तर घटने से कीमतें नरम होने की संभावना है। इससे आम लोगों से लेकर व्यापारिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। एकसमान जीएसटी दर से कीमतों के मोर्चे पर पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जब सभी राज्यों में एकसमान कर व्यवस्था लागू होगी तो एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार का विकास होगा, जो कि जीएसटी के मूलभूत उद्देश्यों में से एक रहा है। इससे राज्यों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। ढुलाई की लागत घटेगी और आपूर्ति शृंखला में भी सुधार होगा। राज्यों की सीमा पर टैक्स बैरियर्स हटने से ढुलाई की गति एवं उसमें तेल की खपत भी कम होगी। इससे समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।

जीएसटी से राज्यों को राजस्व के तत्काल नुकसान की आशंका सता सकती है, लेकिन व्यापक कर दायरे और उससे बढ़ने वाली सक्षमता से लाभान्वित होकर उसकी क्षतिपूर्ति संभव है। जीएसटी परिषद राज्यों के बीच कर राजस्व का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित कर सकती है। ऐसे भी किसी संभावित क्षति की पूर्ति की जा सकती है। समय के साथ इसके माध्यम से बढ़ने वाली सक्षमता एवं अनुपालन सुधार से भी समग्र कर संग्रह में बढ़ोतरी के आसार बनेंगे। पेट्रोलियम उत्पादों पर कर घटाने से उपभोक्ताओं को सस्ते ईंधन का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे महंगाई पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि देश भर में तमाम वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत का पेट्रोलियम उत्पादों की दरों से बड़ा सरोकार होता है। सस्ते परिवहन और उत्पादन लागत से तमाम वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा, जिससे जनता को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा।

इसलिए यह समय की मांग है कि राज्यों को एकीकृत टैक्स सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और देश भर में करों के ढांचे को सुगम बनाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए। इससे जहां जीएसटी के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ेंगे, वहीं एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार के लिए आधार बनने के साथ ही आर्थिक सक्षमता की तस्वीर भी बेहतर होगी। इस परिवर्तन की राह में कुछ तात्कालिक चुनौतियां जरूर दस्तक देंगी, लेकिन इसके बड़े दूरगामी लाभ मिलेंगे। इससे जनता को सस्ते पेट्रोलियम उत्पादों का लाभ मिलेगा, वहीं राजस्व व्यवस्था सुसंगत बनेगी। इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी ढांचे का हिस्सा बनाने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख एवं सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

देशहित में एक राष्ट्र-एक चुनाव

केसी त्यागी

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन यह समय की मांग है

देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर कुछ दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक ने इस बहस को नए सिरे से छेड़ दिया है। बैठक में इस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा जरूर हुई, लेकिन विमर्श और आम सहमति की राह बनती नहीं दिखी। इसे लेकर विपक्ष भी दोफाड़ दिखा। कांग्रेस, सपा, बसपा और डीएमके समेत 16 दलों का बैठक से दूर रहना इस मुद्दे को पूर्णतया खारिज करने जैसा है, जबकि बैठक में शामिल एनडीए के घटक दलों समेत 21 दलों का समर्थन इस विचार को तेज गति प्रदान करने की पहली सफल कोशिश है। सीपीआइ और सीपीएम ने इसके क्रियान्वयन को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन वैचारिक रूप से ये एक साथ चुनाव के समर्थन में हैं। देश के किसी भी मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बहस लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इतने महत्वपूर्ण विषय पर आहूत किसी बैठक से कुछ दलों का दूरी बना लेना लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना है। 'पंचायत से पार्लियामेंट तक' के चुनावों को एक साथ कराए जाने के विचार को किसी पार्टी की पहल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया है। यह रिपोर्ट इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनावों को भी एक साथ कराने की वकालत करती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय विधि आयोग के समक्ष सरकार के इन विधायी प्रयासों का समर्थन किया था। 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' अवधारणा भारत में संसदीय, राज्य और स्थानीय सहित सभी चुनावों को एक निश्चित अंतराल, आमतौर पर हर पांच साल में आयोजित करने की वकालत करती है। भारतीय राजनीति में एक साथ चुनाव कराने का यह विचार नया नहीं है। इससे पहले 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने की वजह से पहली बार एक साथ चुनाव होने का चक्र बाधित हुआ था। वहीं चौथी लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसकी वजह से 1971 में नए चुनाव हुए। एक साथ चुनाव का विचार पहली बार औपचारिक रूप से भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी 1983 की रिपोर्ट में प्रस्तावित किया था। बाद में भारत के विधि आयोग ने भी इसका समर्थन किया।

ऐतिहासिक पहल पर बने राजनीतिक सहमति। फाइल

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को अमल में लाना देशहित में है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष की चिंता है कि मौजूदा सरकार अपने प्रभाव और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के जरिये लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को प्रभावित करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में स्थानीय मुद्दे गौण हो सकते हैं, लेकिन यह भय व्यर्थ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन उसके तुरंत बाद कई विधानसभा चुनावों में उसे पराजय मिली। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में भाजपा को सात सीटों पर मिली बढ़त और विधानसभा में बीजद को बहुमत मिलना भी यही जाहिर करता है। दरअसल देश और प्रदेशों के अपने-अपने मुद्दे संबंधित चुनावों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह राशि किसी दल की नहीं, बल्कि भारत सरकार के कोष में संचित देश के करदाताओं की है। एक साथ चुनाव से रैलियों, रोड शो, लोकलुभावन व्यय समेत बूथ और अन्य प्रबंधकीय खर्चों में कई गुना कमी आएगी। इससे करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों में हो पाएगा। बार-बार चुनाव होने से उम्मीदवारों द्वारा वहन किया गया अतिरिक्त खर्च भी देश में काले धन के प्रवाह को गति देता है। एडीआर के अनुसार राजनीतिक दलों के कुल चंदे का लगभग 70-80 प्रतिशत हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आता है। मौजूदा चुनावी संरचना में हर साल देश का कोई न कोई राज्य चुनाव में व्यस्त रहता है। इसके चलते चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने से सरकार और मतदाता दोनों के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होते हैं। इस दौरान न तो कोई नई नीतिगत घोषणा हो पाती है, न ही उसका क्रियान्वयन। मंत्रियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों की चुनावी प्रक्रिया में व्यस्तता की वजह से विकास और जनकल्याण के कार्य ठप रहते हैं।

हालांकि तमाम अनुशंसाओं के बावजूद एक साथ चुनाव की व्यवस्था करना आसान नहीं है। इस दिशा में एक सवाल यह है कि बहुमत की सरकार यदि अल्पमत में आ जाए तो उस स्थिति में विकल्प क्या होगा? इस स्थिति में निःसंदेह पुनः चुनाव की कवायद प्रचलन में है। एक साथ चुनाव कराने के लिए भंग लोकसभा या विधानसभा को शेष अवधि तक के लिए स्थगित रखना या फिर बहुमत खो चुकी सरकार का सत्ता में बने रहना भी लोकतांत्रिक जनादेश के लिए अपमानजनक होगा। संविधान के अनुच्छेद-356 के उपयोग तथा उसके बाद की दशा भी चिंता का विषय होगी। जहां तक संविधान में बदलाव कर इस नई व्यवस्था को गति देने का विषय है तो इसमें संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान परिदृश्य में चुनौतीपूर्ण है। इस क्रम में कई राज्य सरकारों की कुर्बानी पांच वर्ष के कार्यकाल से पहले देनी पड़ सकती है। इसलिए प्रस्तावित सिफारिशों के लिए आम सहमति अनिवार्य है। यह पहल ऐतिहासिक है। इसलिए इसकी दूरगामी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा।

(लेखक जदयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कर्म का महत्व

संसार में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें ईश्वर जीव को मनुष्य योनि इस अभिप्राय से देता है कि वह विवेक द्वारा संसार के जीवन-मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परब्रह्म में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लेगा। संसार के सभी जीवों में विवेक केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, जिसके द्वारा वह अपने कर्मों पर नियंत्रण कर सकता है। जीव की पहचान उसके कर्मों से होती है। मनुष्य संसार को अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है। इंद्रियां अनुभव की हुई चेतना को व्यक्ति के मन तक पहुंचाती हैं। इसके बाद मन इंद्रिय तृप्ति के लिए उस वस्तु को कर्म द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब वह संबंधित वस्तु को प्राप्त करने में असफल होता है तब उसके अंदर क्रोध जागृत होता है, जिसके बाद उसका विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक समाप्त होने पर उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि शरीर त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है तो वह संसार में सुखी रहकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

इंद्रियों के वेग को रोकने के लिए योग के जरिये मन तथा कर्म पर निरंतर संयम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार नियंत्रित मन शुभ और निष्काम कर्म की तरफ प्रेरित होता है। इसके बाद ही मनुष्य समाधि द्वारा अपनी चेतना को परम चेतना में विलीन कर सकता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। जो लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर शुभ कर्म करते हैं वे मानव जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं और जो बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं वे 84 लाख योनियों के फेर में फंसे रहते हैं।

इसको देखते हुए ही मानस में कहा गया है- 'सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईसु देइ फलु हृदयं बिचारी॥' यानी शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचारकर फल देता है, जो कर्म करता है, वही फल पाता है। यही वह मंत्र है, जिसे आत्मसात करके हम अपने जीवन को सुगम एवं सार्थक बना सकते हैं।

कर्नल शिवदान सिंह

जहरीली शराब से मौत का सिलसिला

अली खान

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 100 से भी अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। यह बेहद चिंताजनक बात है कि देशभर में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके बावजूद देश में जहरीली शराब पर पूरी तरह शिकंजा कसा नहीं जा सका है। देश के कई राज्यों की सरकारों ने शराबबंदी की है। फिर भी अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों की मानें तो देश में नकली शराब के सेवन से वर्ष 2016 में मौत के 1,054 मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2017 में इससे 1,510, वर्ष 2018 में 1,365, वर्ष 2019 में 1,296, वर्ष 2020 में 947 और वर्ष 2021 में 782 लोगों की जान गई। 2016 से 2021 तक छह साल की अवधि में नकली शराब ने भारत में कुल 6,954 लोगों की जान ली।

शराब न केवल सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी बिगाड़ने का काम कर रही है

इस लिहाज से नकली शराब के सेवन से देश में प्रतिदिन औसतन तीन से अधिक लोगों की मौत हो रही है। आखिर जहरीली शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने में सरकारें नाकाम क्यों साबित हो रही हैं? जहरीली शराब लोगों की सेहत के साथ कब तक खिलवाड़ करती रहेगी?

शराब के नशे ने न केवल लोगों की सेहत पर कुठाराघात किया है, बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी बिगाड़ने का काम किया है। देश में अवैध और जहरीली शराब से होने वाली मौतों के चलते बड़ी संख्या में महिलाओं के सुहाग उजड़ रहे हैं। साथ ही बच्चे अनाथ हो रहे हैं। लिहाजा सरकारों को जहरीली शराब पर शिकंजा कसने के लिए आगे आना चाहिए। जब कच्ची शराब को अधिक नशीली बनाने के उद्देश्य से इसमें यूरिया और आक्सीटोसिन जैसे केमिकल मिला दिए जाते हैं तब मिथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। इससे शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं। लिहाजा व्यक्ति की मौत हो जाती है।

शराब का जहरीला होना सिर्फ हादसा नहीं है, व्यवस्था में कहीं न कहीं खोट भी है। इसका खामियाजा समाज को भुगतान पड़ रहा है। आज शराब माफिया पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रशासन सख्ती बरते और संवेदनशीलता अपनाए तो अवैध रूप से शराब बनना बंद हो सकती है और मौतों का सिलसिला भी थम सकता है। शराब पीना एक व्यसन है। व्यसन को महज कानून बनाकर रोका नहीं जा सकता। इसके लिए सरकारी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ समाज तथा परिवार को भी अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। शराबबंदी जन भागीदारी के साथ ही सफल हो सकती है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

परीक्षा आयोजन में हो आवश्यक सुधार

'प्रश्नों के घेरे में परीक्षाएं' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं, उन पर अमल करने की जरूरत है। केवल कड़े कानून बना देने भर से पेपर लीक करने वाले अपराधियों के दुस्साहस को नहीं तोड़ा जा सकता। इस देश का कानून किस गति से काम करता है, यह जगजाहिर है? ऐसे में परीक्षा आयोजन में बेहतर आधुनिक तकनीक को अपनाकर ही उसमें सेंधमारी करने वाले अपराधियों के हौसले को पस्त किया जा सकता है। इसके लिए परीक्षा नियामक संस्थाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होगा। पेपर लीक की आशंका तब और अधिक बढ़ जाती हैं जब एनटीए जैसी परीक्षा नियामक संस्थाएं परीक्षा आयोजन के लिए ठेके पर काम करने वाली बाहरी एजेंसियों पर निर्भर हो जाती हैं। केंद्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि उनके अधीनस्थ सभी परीक्षा नियामक संस्थाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है। पेपर लीक या अन्य किसी अनियमितता की वजह से प्रतियोगी परीक्षा के निरस्त होने पर परीक्षा नियामक संस्था की साख पर तो बट्टा लगता ही है, इसके साथ ही परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्रों की मनःस्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। एनटीए द्वारा आयोजित नीट-यूजी में गड़बड़ी के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा का पेपर लीक हो जाना बेहद शर्म की बात है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे विपक्षी दलों को सरकार पर हावी होने का अवसर मिल रहा है। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को फूलप्रूफ बनाने के लिए परीक्षा आयोजन की वर्तमान पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

शिक्षा के अनदेखे पहलू

मौजूदा परीक्षा प्रणाली छात्रों की वास्तविक क्षमताओं का सही आकलन नहीं करती और इसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि छात्रों पर मानसिक दबाव कम हो और उनके तर्कसंगत सोच और समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। आज की परीक्षाएं मुख्यतः याददाश्त पर आधारित होती हैं, जिससे छात्रों पर अत्यधिक तनाव पैदा होता है। क्या यह उचित है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली को छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्नपत्रों में तर्कसंगत और व्यावहारिक प्रश्नों का समावेश जरूरी है ताकि छात्रों की समस्या सुलझाने की क्षमता का परीक्षण हो सके। इसके साथ ही, निरंतर मूल्यांकन और परियोजना आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना चाहिए। इससे न केवल छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा, बल्कि उनकी विभिन्न योग्यताओं का भी समुचित आकलन हो सकेगा। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, छात्रों को एक तनावमुक्त और सकारात्मक वातावरण प्रदान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

awanishg30@gmail.com

देश के भविष्य से खिलवाड़

मोदी सरकार ने छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बेईमान लोगों को सबक सिखाने के लिए एंटी पेपर लीक कानून लागू अर्थात 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' अमल में ला दिया है। यह कानून परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कामयाब होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि सरकार इतने लंबे समय तक क्यों युवाओं के करियर को दांव पर लगते हुए तमाशा देखती रही। नीट परीक्षा की गड़बड़ी से पहले भी दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, उसके लिए अगर सख्ती बरती होती तो आज नीट के परीक्षार्थियों के साथ धोखा नहीं होता। शिक्षा प्रणाली के दोष देश के लिए दीमक होते हैं। जिस देश की शिक्षा और परीक्षाओं में दोष आ जाए तो उसकी सारी व्यवस्था में ही दोष आ जाएगा और यह दोष देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

चार महादेशों का तपना

धरती के चार महादेश इतना तप रहे हैं कि लगता है, इस बार गर्मी तमाम कीर्तिमान तोड़ डालेगी। धूप या ताप से होने वाली मौतों को बहुत स्पष्टता से नहीं नापा जा सकता, फिर भी दुनिया में इस साल गर्मी की वजह से हजारों मौतें हुई हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े हैं। सऊदी अरब में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि वहां 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें 70 से ज्यादा तो अकेले भारतीय हैं। वहां 51 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा पारा हाजियों के लिए काल बन जा रहा है। मिस्र में 530 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो भारत में 1 मार्च से 18 जून के बीच 40,000 से अधिक हीटस्ट्रोक के मामले आए हैं और 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए हैं। लू से मौत केवल एशिया और अफ्रीका तक सीमित नहीं है, यूरोपीय देशों में भी मौत हो रही है और अमेरिका में भी। 'यूएस नेशनल ओशनिक ऐंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन' के अर्थ ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक, भूमध्य सागर के पास के देशों को भी प्रचंड उच्च तापमान का सामना करना पड़ रहा है, पुर्तगाल से ग्रीस और अल्जीरिया तक में जंगलों में आग लगी हुई है।

वैज्ञानिक इस बात का एहसास करने लगे हैं कि दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रयास करने पड़ेंगे, तभी अत्यधिक ताप से जीवन बचाया जा सकेगा। अपनी ठंड के लिए विख्यात न्यूयॉर्क का तपना तो और भी चिंताजनक है। जिन शहरों को कभी गर्मियों में खुशनुमा माना जाता था, वैसे शहर भारत से लेकर अमेरिका तक, अपनी पहचान खोते दिख रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में अनेक संस्थानों में शीतलन की व्यवस्था करनी पड़ी है, अनेक स्कूलों में बच्चों को दोपहर से पहले ही घर भेज दिया जा रहा है। अनेक अमेरिकी राज्यों में पारा 45 के पार पहुंच जा रहा है। न्यू मैक्सिको में भीषण गर्मी के चलते 23,000 एकड़ से अधिक भूमि जल गई और 500 से ज्यादा घर नष्ट हुए हैं। दुनिया के अनेक देशों में जंगल जल रहे हैं, जिनकी आग केवल भारी बारिश से ही बुझ सकती है। बढ़ता तापमान संकेत है कि दुनिया धीरे-धीरे असहनीय हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? गर्मी आज बड़ा सवाल है, पर उसका हमारे पास क्या जवाब है?

ऐसे अनेक अमीर देश हैं, जो इस खुशफहमी में हैं कि बढ़ती गर्मी उनका कुछ न बिगाड़ पाएगी और पैसे व ऊर्जा भंडार से वे अपना बचाव कर लेंगे।

हमें गंभीरता से सोचना होगा? ऐसी गर्मी के लिए नेपाल जैसा देश जिम्मेदार है या अमेरिका जैसा सुपरपावर? जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जब छिड़ता है, तब अमेरिकी रवैया देख चिंता होती है। अमेरिका की दलील है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग की कीमत नेपाल जैसा देश भी चुकाए, जबकि भारत जैसे देश चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की लागत अमीर हो चुके देशों को ज्यादा चुकानी चाहिए। एक दौर वह भी था, जब अमेरिका ने जलवायु बचाव से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। अनेक अमीर देश हैं, जो खुशफहमी में हैं कि गर्मी उनका कुछ न बिगाड़ पाएगी, पैसे और ऊर्जा भंडार से वे अपना बचाव कर लेंगे। ऐसे देशों को झुलसाती धूप में खुली आंखों से सच्चाई को परखना और समझना चाहिए। भारत निरंतर गुहार लगाता रहता है, पर हरित तकनीक के हस्तांतरण में अभी भी खूब बाधाएं हैं। हरित तकनीक को महंगा किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को दुनिया के विकासशील देशों में बहुत किफायती हो जाना चाहिए, पर विकसित देश यहां भी अपना व्यावसायिक लाभ देख रहे हैं। वाकई, निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर ही दुनिया को बचाने के प्रयास सफल हो सकते हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 23 जून, 1949

मुकदमे का पटाक्षेप

महात्मा गांधी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट का फैसला लम्बे प्रसंग का पटाक्षेप है। ३० जनवरी १९४८ को की गई महात्माजी की हत्या को लगभग डेढ़ साल होने को आया। इस बीच स्थिति में काफी अन्तर पड़ गया है। वह सांप्रदायिक उन्माद जो आजादी के साथ विभाजन की देन के रूप में सामने आया था, अब हल्का पड़ गया है। अपने राष्ट्र को असांप्रदायिक बनाने के उद्देश्य की ओर हम दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। अतः अतीत पर हम संतुलित विचार कर सकते हैं, जो न्याय पर पहुंचने का उत्तम साधन है। ऐसे वातावरण में हुआ हाईकोर्ट का निर्णय निश्चय ही उपयुक्त होना चाहिए और यह उपयुक्त है।

३० जनवरी १९४८ को हुई महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा २७ मई १९४८ को इसी काम के लिए नियुक्त विशेष जज श्री आत्माचरण की अदालत में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में शुरू हुआ था और हत्या के ११ महीने बाद ३० दिसम्बर १९४८ को समाप्त हुआ। विशेष जज ने निर्णय दिया कि महात्मा गांधी की हत्या मिल-जुलकर किये गये षड्यंत्र का परिणाम है और विचाराधीन ९ अभियुक्तों में से दो श्री सावरकर तथा मुखबिर बाडगे को तो उन्होंने छोड़ दिया, बाकी सात को दंड दिया। इनमें से नाथूराम गोडसे व नारायण आप्टे को फांसी और विष्णु रामचन्द्र करकरे, मदनलाल, शंकर किश्तैया, गोपाल विनायक गोडसे व डा. दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे को आजन्म कारावास की सजा दी गई। इसी सजा के विरुद्ध पूर्वी पंजाब हाईकोर्ट में अपील की गई, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट की पूरी बेंच ने २ मई से ६ जून १९४९ तक २६ बैठकों में करके २१ जून को फैसला दिया है।

जस्टिस भण्डारी, जस्टिस अछरूराम और जस्टिस खोसला की पूरी बेंच का यह सर्वसम्मत निर्णय है कि महात्मा गांधी की हत्या 'पूर्वनिश्चित, निर्मम और निर्दय' थी। और जहां तक षड्यंत्र का सवाल है, जस्टिस भण्डारी का कहना है, ''इस मामले में जो बहुत सी शहादतें मेरे सामने आई हैं उनसे मेरे दिभाग में जरा भी शक नहीं रहता कि डा. परचुरे और शंकर के अलावा और सब बंदियों ने महात्मा गांधी को मार डालने का आपस में निश्चय किया था।'' शेष जजों ने जस्टिस भण्डारी के निष्कर्ष से अपनी पूर्ण सहमति दर्शाई है... और विशेष जज द्वारा दी गई सजा को बहाल रखा है।

रोजगार के सवाल से जूझना ही होगा

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

मुफ्त राशन, मुफ्त गैस और मुफ्त घर से अब काम नहीं चल पाएगा। लोगों को रोजगार चाहिए। सरकार यह लक्ष्य कैसे हासिल करेगी, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है।

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लगता है कि रोजगार फिर एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। सरकार के आलोचकों को लगता है कि बेरोजगारों का गुस्सा ही चुनाव नतीजों में सामने आया है। जाहिर है, सरकारी पक्ष भी इस तरफ से कान बंद करके नहीं बैठ सकता। खास बात यह है कि तमाम परेशानियों के बावजूद भारत लगातार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और, इस बात पर तमाम विद्वान एकमत हैं कि आने वाले कम से कम दस-पंद्रह साल तक भारत में तरक्की की रफ्तार इतनी या इससे तेज ही रहने वाली है। ऐसे में, नौजवानों की उम्मीद भी बढ़ती है, लेकिन यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि रोजगार का मतलब नौकरी नहीं है, और सिर्फ सरकारी नौकरी तो कतई नहीं।

जीडीपी में आठ प्रतिशत की जबर्दस्त बढ़त दर हासिल करने के बाद भी बेरोजगारी भारत की बड़ी समस्याओं में एक बनी हुई है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही यह बात साफ है कि राजनीतिक तालमेल से निपटने के बाद इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी रोजगार का इंतजाम! पिछले बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसले हुए, उनका ब्योरा देते हुए रोजगार पर खास जोर दिखाई पड़ा। महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट की मंजूरी के साथ बताया गया कि इससे 17 लाख रोजगार पैदा होंगे। 76,000 करोड़ रुपये के खर्च से बनने वाला यह बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। मगर इस खुशखबरी के साथ यह चिंता भी खड़ी हो जाती है कि तब करोड़ों रोजगार जुटाने के लिए कहां-कहां कितना-कितना खर्च करना पड़ेगा?

भारत सरकार की पे रिसर्च यूनिट सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के वेतन-भत्तों पर खर्च का ब्योरा जारी करती है। उसकी वेबसाइट पर आखिरी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-21 की लगी है। इसके हिसाब से 1 मार्च, 2021 को केंद्र सरकार में सभी वर्गों के कुल 41,11,146 कर्मचारियों के पदों की मंजूरी थी, लेकिन इनमें से 9,95,803 पद खाली थे। यानी, 24.22 प्रतिशत खाली पद भरे नहीं जा सके थे। उसके बाद का आंकड़ा अभी सामने नहीं है। मगर इस साल की शुरुआत में रेलवे भर्ती के मामले पर जैसा बवाल मचा, वह दिखाता है कि नौजवान कितने बेकरार हैं।

अभी एक समाचार एजेंसी ने देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों से सवाल पूछे, तो उनमें से 91 फीसदी का जवाब था कि नई सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के सवाल का हल तलाशना ही होगा। उनके हिसाब से भी समस्या विकट हो रही है, क्योंकि तेज आर्थिक विकास के बावजूद उस अनुपात में रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की 'इंडिया इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट' ने पिछले बीस साल के दौरान भारत में रोजगार की तस्वीर खींचने की कोशिश की है। हालांकि, इन वर्षों में कोरोना काल के लगभग गर्त में गए साल भी शामिल हैं। फिर भी, इसमें एक बड़ी चिंता सामने आती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में देश की आबादी का लगभग 64 फीसदी हिस्सा 15 से 59 साल की उम्र के बीच है। इसी उम्र के लोगों को कामकाजी आबादी माना जाता है। हालांकि, इस पर विवाद हो सकता है, क्योंकि 18 से कम उम्र के लोगों को रोजगार में होना नहीं चाहिए और आजकल 60 पार करने के बाद भी कई लोग तरह-तरह के काम करते रहते हैं। फिर भी, यदि इसी परिभाषा को मान लें, तो सोचने वाली बात यह है कि 2011 में आबादी का 61 फीसदी हिस्सा ही ऐसे लोगों का था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक, 2036 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 65 फीसदी हो जाएगी। हर साल 80 लाख से ज्यादा नौजवान इस बिरादरी का हिस्सा बन रहे हैं।

इसमें थोड़ा और बारीकी से झांकें, तो पता चलता है कि साल 2000 में जहां आबादी के इस हिस्से में सिर्फ 18 फीसदी लोग पढ़े-लिखे थे, वहीं 2022 तक यह गिनती बढ़कर 35 फीसदी हो चुकी थी। जबकि, दूसरी तरफ इसी दौरान कमाई कर रहे नौजवानों की गिनती 52 फीसदी से गिरकर 37 फीसदी पर पहुंच गई थी। इस रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि बेरोजगारी का संकट मुख्य रूप से नौजवानों की समस्या है। 2022 में कुल बेरोजगारों में 82.9 प्रतिशत नौजवान थे, जबकि पढ़े-लिखे नौजवान इस बेरोजगारों की फौज का 65.7 फीसदी हिस्सा हो चुके थे। चिंता को और बढ़ाने वाला आंकड़ा यह है कि 12वीं क्लास या उससे ज्यादा पढ़ने के बाद भी जो लोग बेरोजगार हैं, उनमें से 76.7 फीसदी महिलाएं या लड़कियां थीं।

साफ है, ये सारे लोग सरकारी या निजी नौकरी के भरोसे तो हैं नहीं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जो स्वरोजगार करते हैं और वे भी हैं, जो अपने परिवार के कारोबार में हाथ बंटाते हैं। दीगर यह भी है कि भारत की आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है और 47 फीसदी खेती या उससे जुड़े कामकाज के भरोसे है। यह जानकारी 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण में थी। मगर अब बेरोजगारी की जद्दोजहद में सबसे बड़ी व कमजोर कड़ी है खेती के अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले या काम की तलाश में लगे लोग। इन्हीं का हाल बताने के लिए सरकार का सांख्यिकी विभाग नियमित रूप से सर्वेक्षण करता रहता है। शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही रिपोर्ट आती है, जबकि गांवों के लिए सालाना।

इसी महीने सरकार ने 2021-22 और 2022-23 के सालाना सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। 2022-23 की रिपोर्ट में बेरोजगारी की दर 3.2 प्रतिशत दिख रही है, यानी अमेरिका से भी कम, पर इसी में 15 से 29 साल की उम्र के लोगों में यह 10 फीसदी के चिंताजनक स्तर पर दिख रही है। 2017-18 के आंकड़े से मिलाएं, तो पता चलता है कि यह 17.8 प्रतिशत की ऊंचाई से गिरकर 10 फीसदी पर आई है। दूसरी तरफ, शहरी रोजगार पर तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जनवरी से मार्च के दौरान 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी की दर 17 फीसदी पर पहुंच गई है। यह पिछले साल से थोड़ी कम है, मगर खतरे के निशान से काफी ऊपर है।

यहां यह बात भी समझनी चाहिए कि मुफ्त राशन, मुफ्त गैस और मुफ्त घर से अब काम नहीं चल पाएगा। लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार भी ऐसा, जिससे उन्हें अपनी इज्जत और हैसियत बढ़ने का एहसास हो। सरकार यह लक्ष्य कैसे हासिल करेगी, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। मगर इतना साफ है कि इस समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। इससे मुंह मोड़कर गुजारा नहीं हो सकता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नीति और नियम जापान से सीखे भारत

यहां स्कैन करें

जसप्रीत बिंद्रा | तकनीक विशेषज्ञ

साल 1991 में भारत ने अपने पूर्वी पड़ोसियों और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और सामरिक संबंध बनाने के लिए 'लुक ईस्ट पॉलिसी' यानी 'पूरब की ओर देखो नीति' बनाई थी, जो पश्चिम पर निर्भरता संबंधी पुरानी सोच से अलग थी। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई वाले इस दौर में यह विचार कर रहा है कि इस ताकतवर नई तकनीक को उसे कैसे बढ़ावा देना चाहिए और किस तरह इससे जुड़े नियम बनाने चाहिए, क्योंकि एआई हमारे उद्योग, समाज और भू-राजनीति को नया रूप दे सकती है। निस्संदेह, एआई से बड़े आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने की उम्मीद है, पर कॉपीराइट, मानवाधिकार हनन, निजता व निष्पक्षता से जुड़ी आशंकाएं भी कायम हैं। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि एआई को नियमों के अधीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

मेरा मानना है, भारत को पूरब की ओर देखना चाहिए और जापान से सीखना चाहिए, जो ऐसे नियम बना रहा है, जिसमें नवाचार का माहौल बनाने के साथ-साथ सुरक्षित एआई के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। उसकी नजर में एआई ऐसी प्रेरक चीज है, जो नवाचार और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में दशकों से आए ठहराव को दूर कर सकती है। 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के लिए हम भी एआई से इसी तरह मदद ले सकते हैं। दरअसल, जापान ने 2023 के जी-7 शिखर सम्मेलन का फायदा उठाया, जिसमें 'हिरोशिमा एआई प्रोसेस' (एआई सिस्टम बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमन को बढ़ावा देने वाला फ्रेमवर्क) द्वारा एआई को विनियमित करने के लिए प्रावधान बनाने पर जोर दिया गया। इसमें दो दृष्टिकोण सामने आए- पहला, यूरोपीय संघ या चीन के नियमों की तरह सख्त कानून बनाया जाए, और दूसरा, पारंपरिक सिद्धांतों और निगरानी को दरकिनार करके अपेक्षाकृत नरम कानून बनाना। जापान ने दूसरा नजरिया चुना।

जापान का नजरिया एआई का संतुलित विकास करना है, जो हमारे सामाजिक ताने-बाने के हिसाब से भी मुफीद हो सकता है।

स्टेलेनबोश यूनिवर्सिटी की इंगे ओडेन्डाल ने अपने शोध-पत्र में उसके प्रयासों के बारे में बताया है। इनमें पहला है, सरकार का सुविधा-प्रदाता के रूप में काम करना। जापान की सरकार नवाचार से जुड़े प्रयासों को अपनी मुट्ठी में कैद करने के बजाय उसके लिए सुविधा मुहैया कराने वाली संस्था बनना पसंद करती है। वह निजी क्षेत्र को अगुवा मानती है और अपने विभागों को उनकी मदद के लिए सक्रिय रहने को कहती है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमारी सरकार को निजी क्षेत्र को केंद्र में रखना चाहिए और तमाम मंत्रालयों के जरिये सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा है, वित्तपोषण और निवेश पर ध्यान। जापान ने जेनरेटिव एआई, घरेलू डाटा सेंटर और स्थानीय चिप उत्पादन के लिए एक बड़ा कोष बनाया है। इससे तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी में प्रोत्साहन व सब्सिडी प्रदान की जाती है। भारत में भी इस तरह का कोष है, जो इंडिया एआई योजना के तहत बना है। मगर अंतर यह है कि इसका उपयोग प्रसंस्करण इकाइयों की खरीद में अधिक हो रहा है, न कि जापान की तरह नवाचार में।

तीसरा है, सरकार, अकादमिक और उद्योग में सामंजस्य। 'एआई जापान आरऐंडडी नेटवर्क' देश के तमाम विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, निजी क्षेत्र व वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ मिलकर एआई शोध व कंपनियों से जुड़ी नीतियों की सिफारिश करता है। भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। मजबूत निजी क्षेत्र के साथ-साथ वैश्विक तकनीक में हमारा खास दखल है। चौथा है, घरेलू क्षमता का निर्माण। जापान अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) बनाने की सोच रहा है। भारत में भी ऐसे कई मॉडल बन रहे हैं और उनको सरकारी मदद से लाभ होगा। आधार, यूपीआई जैसे कदमों से पता चलता है कि आम लोगों को केंद्र में रखकर हम तकनीक विकसित कर सकते हैं। इसी तरह जेनरेटिव एआई को आम जनजीवन में उतारा जा सकता है। और पांचवां है, दार्शनिक नजरिया। निजता और डाटा उपयोग जैसे बुनियादी मसलों पर पूरब और पश्चिम की सोच अलग है। पश्चिमी देशों के लिए जहां निजता का अर्थ है, अकेले रहने का अधिकार, वहीं पूरब में इसका मतलब है, सामूहिक व सामाजिक निजता। ऐसे में, हमें एआई नियमन को लेकर उचित ही जापान की ओर देखना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति मिलती है और जो नवाचार व नियमन को लेकर संतुलित नजरिया भी रखता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

क्या टूट रहा भरोसा

अमेरिका में एक कंपनी है एडेलमैन, जो हर साल नागरिकों के भरोसे का स्तर मापती है। जाहिर है, यह काम कठिन है और पेचीदा भी, क्योंकि भरोसा या विश्वास एक अदृश्य भावना है, उसका सामाजिक अन्वेषण कैसे किया जाए? लेकिन यह कंपनी लोगों को प्रश्नोत्तरी भेजकर जायजा लेती है। वह अधिकतर युवाओं, बीस साल के आसपास के लोगों से जवाब लेती है। एडेलमैन के अध्ययन में पता चला है कि साल 2024 में लोगों के भरोसे का मीटर डाउन हो रहा है।

इन दिनों भरोसा किसी परमात्मा या धर्म या धर्मगुरु में नहीं, बल्कि इन चार संस्थानों में पाया गया है : उद्योग, प्रशासन, कल्याणकारी संस्थाएं व मीडिया। लेकिन ये भी अब सभी लोगों का भरोसा खो रहे हैं। विरोधाभास यह है कि तेजी से हो रही वैज्ञानिक खोजें समृद्धि के एक नए युग का वादा करती हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप इतना अधिक है कि अब इनमें भी भरोसा कम होता जा रहा है। एक तरफ समाज समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर लोगों के दिलों में आशंकाएं और चिंताएं बढ़ गई हैं।

दरअसल, भरोसा या विश्वास हृदय का गुण है। एडेलमैन के सर्वे में यह पाया गया है कि लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा उनके मित्र और परिजनों में है, जिन्हें वे जानते हैं और जिनका उन्हें अनुभव है। यह तथ्य मनोविज्ञान के बहुत करीब है। हमारा मन उसी पर भरोसा रखता है, जिसको वह जानता है। योग में भी ज्ञान के तीन चरण बताए गए हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन। प्रत्यक्ष, यानी अपने अनुभव से सीखना। दूसरा है, तर्क और सोचकर अनुमान लगाना, और तीसरा, भरोसे के व्यक्ति द्वारा उसे सुनना। यह आज भी सही है।

आम जिंदगी में भी हमने देखा है कि चाहे डॉक्टर हो या दुकानदार या दादी-नानी हों, जिस पर विश्वास होता है, उसी की बात का असर भी होता है। यह भरोसा एक रहस्य है; अकारण, अतर्क्य और अप्रयास होता है। यह अंदर कहीं छिपा हुआ रहता है, लेकिन इसी के दम पर लोग जीते हैं। जैसे हृदय अंदर धड़कता रहता है, बाहर पता नहीं चलता, लेकिन वह स्वस्थ हो, तो ही हम जी सकते हैं। वह जीवन की कील है। कभी आपने गौर किया है, आजकल सामाजिक असुरक्षा, असंतोष, क्रोध, मवाद की तरह क्यों फूटता रहता है? क्योंकि मूलतः यह भरोसे की कील डांवाडोल हो गई है।

विश्वास की बेल उगती है हृदय में और वहीं वह शांति व प्रेम के सिंचन से पनपती है। शरीर को जैसे प्राण-वायु की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हृदय को भरोसे की जरूरत है।

ध्यान रहे, विश्वास की बेल उगती है हृदय में और वहीं वह शांति व प्रेम के सिंचन से पनपती है। लेकिन यह रास्ता ही हम भूल गए है। शरीर को जैसे प्राण-वायु की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हृदय को विश्वास या भरोसे की जरूरत है। अब किसी पर भरोसा ही न हो, तो यह उखड़ी-उखड़ी सी जिंदगी लेकर क्या करें?

अमृत साधना

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति

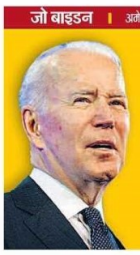

चाहे कोई कितनी भी कोशिशें कर ले, अश्वेतों के इतिहास और उनकी गाथाओं को हमारे देश (अमेरिका) की अंतरात्मा से न कभी मिटाया जाएगा, न नकारा जाएगा और न ही कभी प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

पुरस्कारों से जुड़ी नियमावली में बदलाव जरूरी

साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार को लेकर विवाद स्वाभाविक है। इसकी नियमावली में आखिर कहां उल्लिखित है कि अंतिम तिथि के बाद प्रकाशित किताबों को ज्यूरी अनुशंसा करके पुरस्कार की रेस में शामिल कर सकती है? जब ज्यूरी के पास यह विशेषाधिकार है ही नहीं, तो वह कैसे पुरस्कार की दौड़ में किताबों को शामिल कर रही है? ज्यूरी के इस मनमानेपन को अकादेमी रोक क्यों नहीं रही? यह बतलाता है कि अकादेमी भी कहीं-न-कहीं इसमें संलिप्त है। प्रश्न यह भी है कि आवेदन के लिए अंतिम तिथि का नियम क्यों रखा गया है? अगर नियम रखा गया है और आवेदन के बाद किसी भी लेखक की किताब, चाहे लेखक खुद भेजता हो या प्रकाशक, उसे क्यों माना जाए? क्या यह भेजी गई प्रविष्टियों और लेखकों के साथ अन्याय नहीं है? मान लें, किसी युवा लेखक की पुस्तक तय तिथि के बाद आती है। वह पुस्तक अपने विधा और विषय में बेहद महत्वपूर्ण, समय-समाज सापेक्ष और वैचारिक है, किंतु लेखक की पहुंच न प्रकाशक तक है, न ज्यूरी में बैठने वाले किसी सदस्य तक। तब उस प्रतिभावान युवा लेखक और उसकी रचना की गुणवत्ता का क्या होगा? दूसरी बात यह भी है कि अगर तय तिथि तक भेजी गई रचनाओं को आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, तो सकारण उसका लिखित प्रमाण भी हो!

इतना ही नहीं, जब नियमावली में अनुशंसा का प्रावधान ही नहीं है, तब ज्यूरी द्वारा अनुशंसित पुस्तक पर अकादेमी विचार होने क्यों देती है? अगर प्रथम और द्वितीय चरण की समितियों से अनुशंसा लेनी है, तो सर्वप्रथम नियमावली में संशोधन होना चाहिए। संशोधन के बाद प्रथम और द्वितीय चरण की समितियों की अनुशंसा उसी तिथि तक स्वीकार करना चाहिए, जिस तिथि तक लेखक और प्रकाशक का आवेदन स्वीकार किया जाता है। बाद में अनुशंसा स्वीकार करना अकादेमी द्वारा एक गलती को अंजाम देना है। हां, अगर लेखक-प्रकाशक के साथ-साथ उसी पुस्तक को प्रथम और द्वितीय चरण की समितियों ने भी अनुशंसित किया है, तो अकादेमी द्वारा किसी एक के आवेदन या अनुशंसा को हटा देना चाहिए।

पुरस्कार की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए तय तिथि के बाद प्रकाशित रचना को अगले वर्ष के लिए विचार करना चाहिए, न कि उसी वर्ष के लिए। ज्यूरी द्वारा अनुशंसा का प्रावधान पहले नियमावली में कर लिया जाए, उसके बाद अनुशंसित किताब को पुरस्कार की रेस में शामिल किया जाए। यह पारदर्शी प्रकिया होगी। मगर वर्तमान नियमावली में यह प्रावधान नहीं है। उम्मीद है, मौजूदा नियमावली में बदलाव होगा और पुरस्कार प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

कुमार सुशांत, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

साहित्य अकादेमी

साहित्य में विवाद का उठना नई बात नहीं

साहित्य अकादेमी द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों और पुरस्कारों को लेकर होने वाले विवाद कोई नई बात नहीं। इस बार भी अगर भाषा सम्मान और युवा पुरस्कार को लेकर हंगामा मचा हुआ है, तो कोई हैरानी नहीं हो रही। भाषा सम्मान आमतौर पर उन अध्येता या लेखक को दिया जाता है, जिन्होंने गैर-मान्यता प्राप्त भाषा के उत्थान को लेकर कोई बड़ा काम किया हो, या फिर जिनका मध्यकालीन कविता पर उल्लेखनीय काम हो। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने मध्यकालीन हिंदी कवियों- कबीर और जायसी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का काम किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। ऐसे में, भाषा पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विवाद क्यों? इसी तरह, हिंदी में गौरव पांडेय को युवा पुरस्कार दिए जाने पर भी विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह पुरस्कार पार्वती तिर्की, अदनान काफिल या विहाग वैभव में से किसी को मिलना चाहिए था। यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि पुरस्कार मात्र एक है, लेकिन वैकल्पिक नाम तीन-तीन सुझाए जा रहे हैं। वैसे, साहित्य अकादेमी के अन्य भाषायी पुरस्कारों को लेकर भी विवाद होते रहे हैं। जब हिंदी कवयित्री अनामिका को पुरस्कार मिला था, तब भी विवाद के स्वर सुनाई दे रहे थे और जब कवि बद्री नारायण को पुरस्कार देने की घोषणा हुई, तब भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे, जिनका कोई खास महत्व नहीं था।

साहित्य अकादेमी की ज्यूरी के समक्ष एक साथ कम से कम चार किताबें और अधिकतम कितनी भी किताबें विचार के लिए रहती हैं। ज्यूरी के सदस्य सर्वसम्मति या बहुमत से उनमें से किसी एक पुस्तक को पुरस्कार के लिए चुनते हैं, जिनको वे सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। साहित्य के सामान्य पाठकों को भी पता है कि हर व्यक्ति का अपना-अपना पाठबोध होता है और अपनी-अपनी समझ के मुताबिक वे किसी पुस्तक के बारे में अपना मत बनाते हैं। कई बार तो ज्यूरी के सदस्य भी मानते हैं कि अमुक पुस्तक पुरस्कृत किए जाने लायक है, लेकिन एक ही पुरस्कार देने और बहुमत की विवशता के कारण उन्हें किसी एक पर निर्णय लेना पड़ा।

यहां यह भी समझना चाहिए कि साहित्य अकादेमी एक स्वायत्त संस्था है और इसमें अकादेमी के अधिकारी केवल प्रक्रिया के संचालन में हिस्सा लेते हैं। पुरस्कार के निर्णय में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, फिर भी आरोपों का ठीकरा साहित्य अकादेमी पर ही फोड़ा जाता है। साहित्य अकादेमी देश भर के तमाम साहित्यकारों की एक मान्य सम्मानित संस्था है, उसका आदर करने के साथ ही, साहित्यकारों को विवादों से बचते हुए सृजनशीलता और साहित्य पर ही चिंतन करना चाहिए।।

शिव कुमार शिवम, टिप्पणीकार

दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें न ही देखी जा सकती हैं और न ही छुई, उन्हें बस दिल से महसूस किया जा सकता है।

- हेलेन केलर

कानून का घेरा

पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्त्वपूर्ण परीक्षाओं में धांधली, प्रश्न-पत्रों के बाहर आ जाने के मसले पर जिस तरह का रोष देखा जा रहा है, वह स्वाभाविक है। ऐसे हर विवाद के बाद सरकार का यही आश्वासन सामने आता रहा है कि वह मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मगर वर्षों से यह समस्या बदस्तूर कायम है। अब शुक्रवार केंद्र सरकार ने जिस कानून को लागू किया है, उसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और कदाचार पर रोक लगाना है। दरअसल, करीब चार महीने पहले लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को मंजूरी मिली थी और अब इसे कानून की शक्ल में लागू किया गया है। इसके प्रावधानों को बेहद सख्त माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब अलग-अलग स्तर की परीक्षाओं में धांधली पर लगाम लगेगी। हाल में नीट और यूजीसी-नेट की परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के बाहर आ जाने और अन्य गड़बड़ियों से उपजे विवाद के बीच इस कानून को लागू करने के कदम को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

गौरतलब है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है। यों परीक्षा में नकल या प्रश्न पत्रों को समय से पहले ही बाहर निकालना पहले भी गैरकानूनी रहा है, मगर इस कानून के पहले कोई धांधली किए जाने या अपराध होने की स्थिति में उससे निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। अब अगर नकल कराने जैसी अवैध हरकत के आरोप में कोई पकड़ा जाता है, दोषसिद्धि की स्थिति में उसे न्यूनतम तीन से पांच वर्ष तक के कारावास और ऐसे संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से दस वर्ष तक की जेल की सजा दी जाएगी। इसमें न्यूनतम एक करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। हालांकि इस कानून के तहत प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

यह जगजाहिर हकीकत रही है कि अपराधों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी अहमियत कई बार दस्तावेजों में सीमित रहती है। उसे वास्तव में लागू करने को लेकर मजबूत इच्छाशक्ति नहीं दिखती है। जबकि सख्ती से अमल को सुनिश्चित किए बिना कोई भी कानून बेमानी रहेगा। सरकार और संबंधित महकमों को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि नकल का रोग पहले भी गैरकानूनी रहा है, मगर उस पर नकेल कसने के प्रति उदासीनता के क्या कारण रहे? आखिर किन वजहों से स्कूल-कालेज स्तर की परीक्षाओं में नकल की बीमारी नौकरियों और चिकित्सा या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं तक में फैल गई? जबकि पिछले कुछ वर्षों में संवेदनशील परीक्षाओं में आधुनिक और उन्नत तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ा है, साइबर क्षेत्र में नित नए प्रयोगों के जरिए भी बहुस्तरीय निगरानी का तंत्र भी मजबूत बनाया गया है। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर बेहद अहम मानी जाने वाली परीक्षाओं में नकल या प्रश्न-पत्रों के बाहर आने जैसी धांधली को रोकने में सरकार नाकाम रही। अब नया कानून तभी सार्थक साबित हो सकेगा, जब इसे लागू करने को लेकर वास्तव में इच्छाशक्ति दिखाई जाए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अहम परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

सूखते जलाशय

शहरी नियोजन की चपेट में आकर बहुत सारे प्राकृतिक जलाशय पहले ही अपना अस्तित्व खो चुके हैं, अब बचेखुचे संरक्षित जलाशयों पर जलवायु परिवर्तन का प्रकोप पड़ना शुरू हो चुका है। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के डेढ़ सौ प्रमुख जलाशयों का स्तर घट कर महज इक्कीस फीसद रह गया है। भीषण गर्मी का असर सबसे अधिक दक्षिण भारत के जलाशयों पर देखा गया है, जहां बयालीस जलाशय हैं और उनमें जल की मात्रा घट कर सोलह फीसद तक रह गई है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के दस जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का अट्ठाईस फीसद जल रह गया है। यही हाल पूर्वोत्तर के तेईस जलाशयों का है, जिनमें उनकी कुल भंडारण क्षमता का करीब बीस फीसद पानी रह गया है। इसे लेकर जल आयोग की चिंता स्वाभाविक है। पहले ही बरसात कम होने की वजह से इन जलाशयों का पुनर्भरण संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, फिर पहाड़ों पर बर्फ कम गिरने के कारण पहाड़ी इलाकों के जलाशयों में पानी का स्तर लगातार घट रहा है।

प्राकृतिक जलाशय अनेक शहरों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत हैं। मगर समुचित रखरखाव और उनके जलस्रोतों का संरक्षण न हो पाने की वजह से उनमें बरसात का पानी भी समुचित रूप में नहीं पहुंच पाता। जलाशयों में बरसात का पानी ऊंचे इलाकों से पहुंचता है, मगर जब वहां बस्तियां बस जाती हैं, तो उनका जलस्रोत बाधित होता है। बहुत सारे जलाशयों का जल स्तर इसलिए भी घट रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह पिछले कुछ वर्षों से तापमान में लगातार वृद्धि और बरसात का असंतुलित होना भी है। गर्मी की अवधि लंबी होने से पेयजल और दूसरे उपयोग के लिए पानी की खपत बढ़ रही है। ऐसे में जलाशयों का स्तर घटते जाने से उन पर निर्भर शहरों और बस्तियों में जलसंकट बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। लंबे समय से सलाह दी जाती रही है कि प्राकृतिक जलाशयों के रखरखाव और उनके जलस्रोतों को अबाध बनाए रखने की योजनाएं बनानी होंगी। बरसात का पानी उन तक पहुंचता रहे और उनमें गाद वगैरह की सफाई होती रहे, तभी उनके पुनर्भरण की संभावना बनेगी।

तालिबान के प्रति बदलता रुख

चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, यूरोप, यूएई और भारत अब तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं।

ब्रह्मदीप अलूने

हाल ही में तालिबान के महत्त्वपूर्ण नेता सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने शिष्टमंडल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान से मुलाकात की। संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने का भरोसा दिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका आतंकी मानता है और उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने पर उसने एक करोड़ डालर तक का इनाम घोषित कर रखा है। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका का अरब दुनिया में महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार है। हक्कानी की यात्रा गुपचुप भी नहीं हुई है। इसलिए इसका संदेश साफ है कि अब अमेरिका भी तालिबान की साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

अमेरिका के तालिबान के प्रति बदलते रुख में भारत की भूमिका भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सहयोगी हैं। अफगानिस्तान के साथ चीन के आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित जुड़े हुए हैं। अमेरिका का तालिबान सरकार के प्रति कठोर रवैया चीन को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, यूरोप, यूएई और भारत अब तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं।

अमेरिका और यूरोप लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति सजग रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस पैमाने पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती, इसकी राजनीतिक परिस्थितियों में लोकतंत्र की उम्मीदें भी दूर-दूर तक नजर नहीं आतीं। अमेरिका के 2021 में अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद से यह देश तालिबान की गिरफ्त में है और चीन इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। चीन की महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट एंड रोड' परियोजना में अफगानिस्तान की अहम भूमिका है और इसी के मद्देनजर दोनों देशों के बीच 2016 में एक अहम समझौता हुआ था। वहां के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए चीनी कंपनियां पूरी तैयारी कर रही हैं। इन खनिजों में अत्याधुनिक तकनीक के लिए जरूरी माइक्रोचिप में लगने वाले महत्त्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।

अफगानिस्तान में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए संकट बढ़ा रहा है। यह भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के खिलाफ भी है। इसका असर कई बहुउद्देशीय विकास परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। तापी गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के मध्य प्रस्तावित है। एशियाई विकास बैंक की आर्थिक सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन फुट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चारों देशों में की जा सके। चीन इस परियोजना को बाधित कर रूस और ईरान के सहयोग से प्राकृतिक गैस को दक्षिण एशिया तक पहुंचाना चाहता है।

चीन, ईरान और रूस की यह साझेदारी इस समूचे क्षेत्र में अमेरिकी हितों को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका मध्य एशिया में एक सैन्य उपस्थिति भी स्थापित करना चाहता है। यह उसे रूस, चीन और ईरान जैसे प्रतिद्वंद्वियों पर निर्णायक सैन्य बढ़त दे सकती है। चीन का सबसे बड़ा संकट शिंजियांग के पश्चिम की वह सीमा है, जो मुसलिम देशों से मिलती है और यही कारण है कि चीन अफगानिस्तान में सैन्य छावनी भी बनाना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। चीन यह छावनी दूरदराज के पहाड़ी इलाके वाखान कारीडोर के पास बनाना चाहता है। यहां चीन की सीमा

> अफगानिस्तान में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए संकट बढ़ा रहा है। यह भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के खिलाफ भी है। इसका असर कई बहुउद्देशीय विकास परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। तापी गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के मध्य प्रस्तावित है। एशियाई विकास बैंक की आर्थिक सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन फीट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चारों देशों में की जा सके।

अफगानिस्तान से मिलती है। चीन इस इलाके को प्रभाव में लेकर पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन के प्रभाव को खत्म करना चाहता है। चीन का विश्वास है कि उइगर आतंकी इसी कारीडोर से उसके शिंजियांग प्रांत में घुसते हैं। इन सबसे निपटने के लिए चीन तालिबान से मजबूत रिश्ते बना रहा है।

पिछले वर्ष कई चीनी कंपनियों ने तालिबान सरकार के साथ लाखों डालर के व्यापारिक सौदे किए हैं। इस सबके साथ बेजिंग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तालिबान को आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान के दूत के रूप में भी मान्यता दे दी है। अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों पर लगातार और व्यापक हमले किए हैं। तालिबान शासन के तहत, अफगानिस्तान की महिलाओं को अपने देश के राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक जीवन में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। इसके चलते वहां गरीबी और बदहाली से आम जनता परत है। अफगानिस्तान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात का मानना है कि अगर आधी आबादी को भागीदारी से बाहर रखा गया, तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना संभव नहीं होगा। मगर तालिबान वैश्विक आलोचनाओं से बेपरवाह, चीन से आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है।

इन सबके बीच अफगानिस्तान के भू-रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए अमेरिका, भारत और यूरोप के लोकतांत्रिक देश यह बखूबी समझ गए हैं कि अब अफगानिस्तान में प्रतिरोध की कोई मजबूत आवाज दिखाई नहीं देती तथा इस देश में ऐसी ताकत नहीं दिखती कि वह तालिबान से लड़ाई लड़े। तालिबान से सहयोग बढ़ाकर ही अफगानिस्तान में अपने हित सुरक्षित रख जा सकते हैं तथा तालिबान की शासन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगाई जा सकती है। 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद भारत समेत कई देशों ने अफगानिस्तान से सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए थे। भारत भी तालिबान के प्रति अपने रुख में नरमी के संकेत दे चुका है। इस वर्ष 26 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने गणतंत्र दिवस समारोह में अफगान के कार्यवाहक दूत बदरुद्दीन हक्कानी को आमंत्रित किया था। रूस, ईरान, तुर्की और भारत सहित कई अन्य देशों ने न केवल मानवीय परियोजनाओं पर, बल्कि काबुल में अपने राजनयिक मिशनों को फिर से खोलकर भी तालिबान के साथ जुड़ने का प्रयास किया है।

इस समय तालिबान अफगानिस्तान में निरंकुश शासन चला रहा है। वहां सामाजिक और राजनीतिक विरोध न होने से देश गंभीर मानवीय और मानवाधिकार संकट का सामना कर रहा है। व्यापारिक, शैक्षिक और सांविधानिक संस्थानों के बंद होने से न केवल देश में अव्यवस्था बढ़ी है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और आजीविका पर भी संकट गहराया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस देश में मदद तो कर रहा है, लेकिन वह भी तालिबान शासन के संगीनों के साए में हो रही है। तालिबान नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, असहमति पर अंकुश है और किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी को स्वीकार नहीं करना चाहता। संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दुनिया के लोगों की भलाई को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय और मैत्रीपूर्ण सहयोग के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अफगानिस्तान की तालिबान शासन व्यवस्था इस किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया मजबूर होकर तालिबान को स्वीकार कर रही है। जाहिर है, दुनिया की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में मानवाधिकार कहीं पीछे छूट रहा है तथा आर्थिक और सामरिक प्रतिबद्धताएं महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।

केंद्र और परिधि

मीना बुद्धिराजा

जीवन के केंद्र को जब हम किसी सीमित दृष्टि पर निर्धारित कर देते हैं तो उसके परिपूर्ण अर्थ और स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते और उसकी परिधि को सीमित कर देते हैं। प्रकृति के प्रवाह की तरह बहती हुई धारा में जैसे बदलाव और परिवर्तन होता रहता है और उसमें किसी एक जगह ठहराव नहीं, निरंतर आगे बढ़ने का स्वभाव निहित होता है। इसी तरह, जब हम खुद भीतर से बंधन में होते हैं, अपनी स्वतंत्र चेतना से नहीं सोचते तो अपनी वस्तुस्थिति से भी सही संपर्क नहीं बना पाते।

नया विषय अगर अज्ञात नहीं है तो वह नवीन कैसे हो सकता है। अपने भविष्य को दूसरों के अनुसार पहले ही हम निर्धारित कर देते हैं तो वह सिर्फ अतीत हो सकता है, नए का निर्माण नहीं कहला सकता। जीवन में आगे का रास्ता अपनी पूर्वनिर्धारित धारणाओं के खिलाफ जाकर ही मिलता है। विषय को जितना हम तय करना चाहते हैं, वर्तमान स्थिति के उतना ही गुलाम बनते जाते हैं और अपने ही बनाए हुए दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। प्रतिदिन और प्रतिपल कुछ बदलना अपने को ठीक से जानने का अवसर प्रदान कर सकता है, क्योंकि अपने अस्तित्व को जानने का अधिकार सिर्फ मनुष्य जाति को ही मिला है। व्यक्ति के पास अपनी चेतना है, इसलिए उसे चयन का, निर्णय का विकल्प भी मिलता है, जिसे अक्सर हम पहचान नहीं पाते। आत्मावलोकन ही आत्मपरिवर्तन का कारण बनता है और यही विवेक वास्तव में व्यक्ति के जीवन के केंद्र का निर्धारण कर सकता है।

दुनिया मेरे आगे

> एक सही आधार से जीवन को किसी सार्थकता से जीने के लिए पहले स्वयं को ही जानना आवश्यक होता है। जब अपनी संभावनाएं पता नहीं होतीं, तो हम दूसरों के जितना पारिभाषित किए गए पैमाने पर सीमित उद्देश्य को पाने की कोशिश करते हैं और महत्त्वाकांक्षाओं के लिए भी दुनिया के अनुसार ही निर्भर हो जाते हैं।

आत्मनिरीक्षण का जोखिम उठाना आसान नहीं है, लेकिन यही दृष्टि पुनर्निर्माण की और बढ़ा पहला कदम है। इसमें चुनौतियों और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं और जड़ता से मुक्ति भी आखिर एक सही विकल्प की तरफ ले जा सकती है। हम जीवन के अर्थ को गहराई से समझ कर अपनी पहचान के प्रति अधिक सजग और संवेदनशील होकर ईमानदारी से अपने जीवन का अवलोकन और मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे अंधेरे की फोटो खींचने का कोई लाभ और महत्त्व नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी वस्तु और विषय का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, इसी तरह समाज और दुनिया में जो घटित हो रहा है, उसका अनुकरण करते चुपचाप जीना भी उतना ही निरर्थक है, जिसमें अपने जीवन को देखने की कोई स्पष्ट दृष्टि प्राप्त नहीं होती। अपने को गहराई से जानना ही पूर्णता से जीना और अपने प्रति उत्तरदायी होना है, जिसमें हमें अपनी निजता का सौंदर्य दिखाई देता है।

अपने जीवन के केंद्र को जानने के लिए हमें अपनी अंतिम सीमा तक जाना पड़ता है और सभी आयामों को अन्वेषित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में किसी मंजिल तक पहुंचने से पहले जो भी बनी-बनाई सुनियोजित अवधारणाएं और भ्रम हैं, उनमें टूट-फूट का काम भी व्यक्ति का आत्मबोध ही करता है। एक सही आधार से जीवन को किसी सार्थकता से जीने के लिए पहले स्वयं को ही जानना आवश्यक होता है और जिसकी हम उपेक्षा करते रहते हैं। जब अपनी संभावनाएं पता नहीं होतीं, तो हम दूसरों के जितना पारिभाषित किए गए पैमाने पर एक सीमित उद्देश्य को ही पाने की कोशिश करते हैं और अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के लिए भी दुनिया के अनुसार ही निर्भर हो जाते हैं। अपने प्रति मौलिक जिम्मेदारी की अनुभूति ही व्यक्ति की क्षमता और संभावनाओं का विस्तार करती है। जीवन की अपनी परिधि के अंतर्गत उतना ही हम देख पाते हैं, जिसकी अनुमति आसपास का परिवेश देता है, लेकिन आगे जाने के लिए संकीर्ण सीमा से पार जाना पड़ता है जो लकीर पहले से ही निर्धारित करके खींच दी गई है।

समाज और समूह के नियमों द्वारा मनुष्य को वे तमाम बाहरी पहचानें दी जाती हैं जो प्रत्येक जगह बई बनावटी परतों और मुखौटों की तरह उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। सुख-सुविधा, सफलता, व्यवस्था और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर अधिकतर हम जीवन को परखते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी आंतरिक सच्चाई की कसौटी के आधार पर ही जीवन के केंद्र को परखा जा सकता है। कोई दुर्लभ व्यक्तित्व ही औसत जीवन की अपनी इन निजी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ कर एक वास्तविक और सार्थक विकल्प को पाने का प्रयास करता है, क्योंकि जो नई दृष्टि से स्वयं के अस्तित्व को नहीं जानना चाहता। उसका बाहर की दुनिया के लिए जितना भी ज्ञान है, वह गलत और व्यर्थ सिद्ध होगा। जब तक जीवन का यह केंद्र दिखाई नहीं देता, तब तक अंधेरे के प्रसार में रोशनी की दिशा की तरह निरंतर उसे खोजना पड़ता है।

इसे पाने के लिए अपने ही बनाए गए बहुत से बाहर के प्रभावों और बंधनों से मुक्त होना जरूरी हो जाता है और जब अपना वह आंतरिक आधार समझ में आ जाता है तो वही जीवन का स्थायी केंद्र बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास अपना निर्मित स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह भीड़ की मनोवृत्ति पर आश्रित रहना बंद कर देता है और दूसरों के कारण निर्धारित की गई मान्यताओं के प्रभाव से नहीं, बल्कि अपनी उच्चतम चेतना से निर्णय का विकल्प चुनता है, क्योंकि जितनी बार दूसरों के अनुसरण और स्वीकृति के अनुसार काम करने का साधारण रास्ता चुना जाता है, वह भीतर के अज्ञान के अंधेरे को उतना गहरा करता जाता है। अपनी एकाग्र और बोधपूर्ण दृष्टि ही वह कीमती चीज है जो व्यक्ति के जीवन की परिधि में दीपक की तरह हमेशा आलोकित रहती है।

लापरवाही की लपटें

देश के अनेक हिस्सों से आग लगने की खबरें प्रतिदिन आ रही हैं। इन दुर्घटनाओं में जानमाल का बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है कि तापमान में आई तेजी से बढ़ोतरी से शहरों और गांवों में दैनिक उपयोग होने विभिन्न उपकरणों में आग लगने के हादसे हुए हैं। कुछ हादसे लीगों की लापरवाहियों के चलते भी हुए हैं। ये लापरवाहियां निर्धारित मानदंडों का उपयोग न करने की वजह से ही हो रही हैं, जिन पर प्रशासन की ओर से उचित नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। आग लगने पर लोगों में स्वाभाविक रूप से घबराहट फैल जाती है, जबकि उस दशा में संयम की अधिक आवश्यकता होती है। संयमित रह कर आग किस तरह बुझाई जा सकती है उस पर सोचा जाना चाहिए। मकान, दुकान, अस्पताल, फैक्टरी या किसी वाहन में आग लगने पर मदद के लिए तुरंत अग्निशमन विभाग वालों को बुलाना चाहिए। वहां मौजूद लोगों को अपने स्तर पर आग बुझाने के लिए पानी, रेत, कंबल आदि का प्रयोग करना चाहिए। बिजली की आपूर्ति को बंद कर आग के साथ-साथ करंट से होने वाली अनहोनियों को रोका जा सकता है।

- नरेश कानूनगो, देवास, मप्र

बर्बादी का भोजन

भारत में जहां न जाने कितने ही लोग रोज भूखे सो जाते हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वहां शादियों, पार्टियों और समारोह में बेशुमार अन्न की बर्बादी होती है। आज जिंदगी में केवल दिखावा ही रह गया है। ज्यादातर विवाह समारोहों में देखा जा सकता है कि किस तरह खाने-पीने की चीजों की जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा वह दिखावे या बर्बादी का जरिया बनता है। हैसियत के प्रदर्शन या 'स्टेटस सिंबल' के चक्कर में आने वाले मेहमानों से यह पूछना कि कितने लोग आ रहे हैं, बुरा लगता है। भोजन की बर्बादी फिजूल नहीं लगती। सरकार सिर्फ नियम और कानून बना सकती है। जब तक लोग अपना दायित्व समझ कर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक भोजन की व्यर्थ बर्बादी को रोका नहीं जा सकता।

- अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

छूटती खेती

पुराने जमाने में सबसे श्रेष्ठ कार्य कृषि को समझा जाता था। दूसरे नंबर पर वाणिज्य एवं व्यापार था। सबसे अंत में नौकरी संबंधी कार्य आता था। आज हमारे किसान भाई जमीन बेच रहे हैं। खेती योग्य जमीन का रकबा कम होता जा रहा है। गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। किसानों के बेटे अपना परंपरागत कृषि कार्य छोड़कर नौकरी करने लगे हैं। कई परंपरागत व्यवसायियों के बेटे अपने व्यवसायों से मुंह मोड़ कर नौकरियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। भले ही नौकरी में कम पैसा मिलता हो, घर परिवार से दूर रहना पड़ता हो। इस सब असुविधाओं को सहकर भी आज का युवा नौकरी के प्रति दीवाना है। देश का अन्नदाता और व्यवसायी ही जब अपने परंपरागत कार्य से मुंह मोड़ने लगेंगे तो देर-सबेर हमारे देश में विषम परिस्थितियों का निर्माण होने में देर नहीं लगेगी। इस बात को सरकार, जनता, व्यवसायी, आज की युवा पीढ़ी और हमारे किसान भाई जितनी जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर होगा।

- ललित महालकरी, इंदौर

मानवीयता का तकाजा

यों जल संकट का सामना सभी बड़े शहर दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम बात देश की राजधानी दिल्ली के जल संकट की करें तो वहां यह इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जल वितरण और प्रबंधन के नीति-निर्णायक बने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से लेकर दिल्ली जल बोर्ड तक के मुख्यालय वहीं स्थापित हैं। प्रश्न यह भी है कि पानी के लिए काफी पहले पांच पड़ोसी राज्यों (हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली) के बीच हुए समझौते पर बढ़ती आबादी और बदलते परिवेश के मद्देनजर पुनर्विचार अभी तक क्यों नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा पानी की कलह को सुप्रीम कोर्ट तक ले तो जाया सकता है, लेकिन बंटवारे के लिए विशेषज्ञ न होने कारण निपटाया नहीं सकता है! इस भीषण गर्मी में जल बिन जल रहे लोगों के लिए पड़ोसी राज्य यानी हिमाचल और हरियाणा अपना मानवीय चेहरा दिखाते हुए दिल्ली को मानवता के आधार पानी जरूर मुहैया करवाएं।

- मामचंद सागर, रजोकरी, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 24 जून 2024

चीन को मिला जवाब

बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की दो दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों की करीबी को एक बार फिर रेखांकित कर गई। इस यात्रा के दौरान वैसे तो दोनों देशों के बीच 10 समझौतों और सहमतिपत्रों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन ध्यान खींचा तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर भारत द्वारा टेक्निकल टीम भेजे जाने के प्रस्ताव पर बनी सहमति ने। यह सहमति भारत के पड़ोसी देशों में अपना दखल बढ़ाने की चीनी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिहाज से खासी अहम मानी जा रही है।

जटिल मसला | तीस्ता नदी जल बंटवारा दोनों देशों के बीच एक जटिल मसला माना जाता रहा है। 2011 में ही तीस्ता जल बंटवारे के एक फॉर्म्युले पर सहमति बन गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के चलते उस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी।

तीस्ता : भारत-बांग्लादेश में सहमति

चीन की दिलचस्पी | इस पृष्ठभूमि में चीन ने 2020 में तीस्ता नदी के प्रबंधन और संरक्षण में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। इससे जुड़ी भारत की चिंताओं के मद्देनजर मामले की संवेदनशीलता से सभी पक्ष वाकिफ थे। लिहाजा बात खास आगे नहीं बढ़ी। मगर पिछले साल दिसंबर में ढाका में चीन के राजदूत ने फिर इस मामले को उठाया। इस बार चीन ने एक संशोधित प्रस्ताव भेजा जिसमें लागत पहले से कम दिखाई गई थी।

आपसी समझदारी | श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जैसे देशों के उदाहरणों की रोशनी में देखें तो चीन का यह रुख नया नहीं था। लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत के करीबी रिश्तों के मद्देनजर तीस्ता जल बंटवारे को लेकर उभरी असहमति ऐसी नहीं थी कि उससे दोनों देशों के बीच संदेह और अविश्वास की गुंजाइश बनती। स्वाभाविक ही दोनों पक्षों ने समय रहते अलग-अलग स्तरों पर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए अपनी इस समझ को मजबूती दे दी कि साझा हितों से जुड़े मसलों पर तीसरे पक्ष को प्रवेश करने देना ठीक नहीं।

साझा सोच | दोनों देशों की यही साझा सोच तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन के मसले पर भारत की टेक्निकल टीम के बांग्लादेश जाने पर बनी ताजा सहमति में नजर आती है। जानकारों के मुताबिक इसका खास पहलू यह है कि टीम इस सवाल पर भी विचार करेगी कि मॉनसून से मिलने वाले अतिरिक्त पानी के रखरखाव के लिए किसी जलाशय के निर्माण की वास्तव में जरूरत है भी या नहीं। समझा जाता है कि चीन की ओर से बांग्लादेश को यही प्रस्ताव दिया गया था।

रिश्तों में संतुलन | हालांकि शेख हसीना अगले महीने चीन की यात्रा पर जाने वाली हैं। चीन से भी बांग्लादेश के अच्छे आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि बांग्लादेश दूसरे देशों के साथ करीबी बनाते और बढ़ाते हुए भारत की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी नहीं होने देता।

चक्र-व्यू
बात तो गलत नहीं

राहुल पाण्डेय

इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के दिनों में विचरने वाले दो से तीन लोग मैंने मार्क किए हैं। इन्होंने ऐसा कहा था, यह लिखकर लोगबाग उनकी फोटो के साथ सोशल मीडिया से लेकर मेसेजिंग एप्स तक में ठेलते रहते हैं। तब तक, जब तक कि कोई यह न कह दे कि बस कर भाई रामबकस! इनमें भी दो नाम प्रमुख हैं। समझ नहीं आता कि किसे पहले नंबर पर रखूं और किसे दूसरे। एक हैं चाणक्य, तो दूसरे हैं गालिब। इनके अलावा गांधी जी से लेकर गुलजार और महात्मा बुद्ध से लेकर महादेवी वर्मा तक एक लंबी सीरीज भी छिटपुट तरीके से साथ-साथ चलती रहती है। मगर चाणक्य और गालिब के बारे में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फर्जी डायलॉग इनके मुंह से ही बुलवाए गए हैं। कल मित्रवर अनुराग के पास उनके किसी चाहने वाले ने चाणक्य की एक तस्वीर भेजी। इस पर लिखा था कि 'गीता' में 'चाणक्य' ने कहा था कि अनुराग और द्वेष के बीच एक सीमा होती है, जिसमें कभी-कभी मट्ठा भी डालना पड़ता है। ऐसे ही एक और मीम देखा, जिसमें लिखा था कि जब शासक कुशिक्षित होते हैं तो शोधार्थियों का फंड कम कर दिया जाता है। साथ में चाणक्य की फोटो भी चिपकी हुई थी। हाल यह है कि जिसके मन में जो आ रहा है, चाणक्य की फोटो लगाकर चेंपे जा रहा है।

वैसे कभी-कभी मुझे लगता है कि चाणक्य से ज्यादा तो चचा गालिब चेंपे गए हैं। हर टूटे दिल की दरख्वास्त गालिब को चेंपने से शुरू होती है। लेकिन उससे पहले उनके शेर को पटककर तोड़ा जाता है। मुलायजा फरमाइए, 'अलाने ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना फलाने भी थे कुछ काम के'। एक ने तो हद ही पार कर दी। एक बेहद खूबसूरत मोहतरमा की शरमाती हुई तस्वीर में गालिब का नाम इस शेर के साथ चस्पां कर दिया, 'जिसे समझा था हमने हर मर्ज की दवा गालिब, वो भी हमारी खातिर जानलेवा जहर निकले'। कसम से, गालिब होते तो जितना मैं उनको जानता हूं, वो अपनी दाढ़ी पर चाशनी चिपकाकर धीमी मौत के लिए उसमें लाल चींटियां पाल लेते। इस चेंपने के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे कम सजा उनको खुद के लिए मंजूर होती। बात इतने पर ही रुक जाती, तब भी गनीमत थी। लेकिन बात गालिब की हो तो जाहिर है कि और भी दूर तलक जाएगी, गनीमत के भी आगे तक। कल पड़ोसी ने एक मीम वट्सएप पर ठेला, जिसमें गालिब की तस्वीर के साथ लिखा था, 'बदनाम किसी को क्यों करें गालिब, दुश्मन तो अपनों में ही छुपे बैठे हैं।' मैंने पड़ोसी को लिखा, यह गालिब ने नहीं लिखा है। पड़ोसी ने पूरी ढिठाई से जवाब दिया, 'गालिब ने भले ना लिखा हो, मगर बात तो गलत नहीं है?'

एकदा
US में सविनय अवज्ञा

बात 1960 की है। अमेरिका के नसविले (Nashville) शहर के होटलों और रेस्तराओं में गोरे और काले ईसाइयों के बैठने के लिए अलग-अलग सीटें थीं। बैठने की यह व्यवस्था काले रंग के लोगों का अपमान करती थी। यह अपमान जेम्स लासन (James Lawson) नाम के नागरिक से नहीं सहा गया। विरोध के लिए उन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा विचार का सहारा लिया। उन्होंने काले छात्रों को प्रशिक्षित किया कि किस तरह शहर के होटलों और रेस्तराओं में गोरों के लिए आरक्षित सीटों पर लंच के दौरान उन्हें बैठ जाना है और टस से मस नहीं होना है। भले ही पुलिस उन्हें घसीटे, मारे, पीटे और जेल ले जाए। छात्रों ने वैसा ही किया। अलग-अलग बैठने की व्यवस्था को चुनौती देते हुए गोरों के लिए आरक्षित जगहों पर बैठना शुरू किया। नतीजा उनकी पिटाई और जेल। लेकिन एक जत्थे को पीटा जाता, जेल भेजा जाता तो दूसरा जत्था इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देने के लिए होटलों और रेस्तराओं में पहुंच जाता और गोरों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ जाता। आए दिन ऐसी घटनाएं होने लगीं। समाचार पत्रों में भेदभाव की निंदा होने लगी। आखिरकार वहां के मेयर बेन बेस्ट को घोषणा करनी पड़ी कि उनके शहर में होटलों और रेस्तराओं में काले और गोरों के लिए अलग-अलग बैठक व्यवस्था अनैतिक है और इसे समाप्त किया जाता है। जेम्स ने जब कोरिया युद्ध में भाग लेने से इंकार किया, तो अमेरिकी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। 14 महीनों की सजा काट कर जब वह जेल से छूटे तो नागपुर आए और यहीं रहकर महात्मा गांधी के अहिंसा को नजदीक से समझा, परखा और अमेरिका जाकर इसका सफल प्रयोग किया।

संकलन : **हरिप्रसाद राय**

आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की वापसी के साथ ही TDP चीफ का ड्रीम प्रॉजेक्ट चर्चा में आ गया है

क्या आंध्र में सिंगापुर का सपना सच होगा

शैलेंद्र पांडेय

सातवाहन, इक्ष्वाकू, चालुक्य, चोल, काकातिया और रेड्डी - कृष्णा नदी के इस उपजाऊ किनारे ने वक्त के साथ कितने साम्राज्य बनते-बिगड़ते देखे। सदियों तक दक्कन की सियासत यहीं से नियंत्रित होती रही। एक बार फिर से जमीन का वह टुकड़ा सियासी रूप से उपजाऊ हो चुका है। आंध्र प्रदेश में फिर से अंगड़ाई ले रही है अमरावती की कहानी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आंध्र की नई राजधानी के रूप में अमरावती को बसाने की योजना में अब तेजी आएगी।

चंद्रबाबू से उम्मीदें | इस उम्मीद की वजह हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र में उन्होंने वापसी कर ली है और केंद्र में NDA की सरकार भी उनकी पार्टी TDP के बिना नहीं चल सकती। ऐसे में उनका ड्रीम प्रॉजेक्ट अमरावती चर्चा में है। इस इलाके में जमीन के दाम चार गुना हो चुके हैं।

मेगा प्रॉजेक्ट | चंद्रबाबू नायडू जिस अमरावती को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वह हेरिटेज अमरावती नहीं आता जो बौद्ध केंद्र और सातवाहन साम्राज्य की राजधानी के रूप में इतिहास में दर्ज है। इस नए अमरावती का इतिहास शुरू होता है एक दशक पहले से। 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर अलग राज्य तेलंगाना बनाया गया। हैदराबाद को 10 बरसों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी घोषित किया गया था।

आधुनिक शहर | कृष्णा नदी के किनारे गुंटूर जिले में लगभग 217 वर्ग किमी में अमरावती को बसना है। अक्टूबर 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। विधानसभा, राजभवन, हाई कोर्ट, सचिवालय - यहां हर वह चीज बननी थी जो एक राजधानी में होती है। इसे आधुनिक भारत के ऐसे आधुनिक शहर के रूप में डिजाइन किया जा रहा था, जहां कॉमर्स, ट्रेड, गवर्नेंस, नॉलेज, टूरिज्म, मेडिसिन - हर फील्ड के लिए एक्सक्लूसिव जोन होते।

नई राजधानी
- कृष्णा के किनारे बन रहा नया शहर
- 2015 में हुआ था इसका शिलान्यास
- सिंगापुर जैसा रूप देने की योजना

आंध्र को भरोसा | साल 2019 में TDP की हार हुई और YSR कांग्रेस सत्ता में आई। वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार बताते हैं, 'जगनमोहन रेड्डी की सरकार में अमरावती से फोकस हट गया था। ऐसे में चंद्रबाबू को अब सब नए सिरे से शुरू करना होगा। हैदराबाद को डिवेलप करने में भी चंद्रबाबू का ही हाथ है। लोगों को उम्मीदें हैं कि वह अमरावती को भी विकास की राह पर ले जा सकते हैं। आंध्र में ऐसी भावना है कि इस बार केंद्र का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पहले फेज का काम 30 महीने में पूरा होना है।' चंद्रबाबू बड़े प्रशंसक हैं सिंगापुर मॉडल के। वह अमरावती को सिंगापुर की तरह ही डिवेलप करना चाहते हैं, एक ग्लोबल सिटी के रूप में।

AI Image

हलचल शुरू | आंध्र प्रदेश की यह प्रस्तावित राजधानी फिलहाल एक मेगा साइट के रूप में नजर आती है। पांच बरसों बाद TDP की वापसी से यहां हलचल बढ़ गई है। हमारे सहयोगी अखबार ET की रिपोर्ट से पता चलता है कि अमरावती में जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के रहने के लिए बन रहे बंगलों, विधायकों के अपार्टमेंट वगैरह का काम अधूरा है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं लेकिन लोग डेली अप-डाउन करते हैं।

राह की चुनौतियां | TDP ने राज्य विधानसभा की 175 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में चंद्रबाबू एक स्थिर और मजबूत सरकार चला सकते हैं और नई राजधानी को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं होने जा रहा :

- सबसे बड़ी वजह है बजट। जब यह प्रॉजेक्ट शुरू हुआ, तब अनुमान था कि लगभग 50 हजार करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स इससे दोगुने का भी अनुमान लगा रहे हैं। इतना पैसा आएगा कहां से?
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधान के मुताबिक, नई राजधानी बनाने में केंद्र को आंध्र की मदद करनी है। लेकिन, यह मदद राजभवन, विधानसभा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए है, न कि एक पूरा शहर बसाने के लिए।
- केंद्र की NDA सरकार को स्थिर रखने में TDP की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है, लेकिन अगर पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश की मदद करते हैं, तो ऐसी ही मांग दूसरे राज्यों से भी उठ सकती है।
- विशेष पैकेज के मुद्दे पर ही मार्च 2018 में चंद्रबाबू ने NDA का साथ छोड़ा था। वैसे संजय कुमार का कहना है कि आंध्र में चंद्रबाबू जिस तरह के विकास कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए केंद्र का साथ जरूरी है। आमतौर पर दिल्ली के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहते हैं। बीच में थोड़ी बात बिगड़ी थी, पर लगता नहीं कि लंबे समय बाद सत्ता में वापसी कर रहे चंद्रबाबू नायडू फिर कोई अलग रास्ता अपनाएंगे।
- पिछले कार्यकाल में चंद्रबाबू की सरकार ने नई राजधानी के लिए किसानों से लगभग 30 हजार एकड़ जमीन ली थी। बदले में विकसित प्लॉट और 10 बरसों तक वार्षिक भत्ता देने का वादा था। चूंकि प्रॉजेक्ट पांच बरसों तक लटका रहा, तो कई किसान annuity बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

अमरावती को जिन खेतों पर बसाया जा रहा, वे बेहद उर्वर थे। किसानों ने इस भरोसे के साथ खेत दिए थे कि उनकी मिट्टी से आंध्र को नई पहचान मिलेगी। चंद्रबाबू के सामने उस भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती है।

बस आम का रस है और डूब कर जाना है

होली के उतरते रंगों के साथ जब उतरने लगता है हवा का ठंडापन तो धूप की तपन से मुस्कान का झुलसना एक ही चीज रोक पाती है। गर्मी आने के साथ ही देश के हर कोने में, हर शहर और हर गांव में, घुल जाती है इसकी मिठास। यह मिठास है आम की, जो अपनी मौसमी उपस्थिति से ही खुशियां बिखेरता है।

आम सिर्फ फल नहीं, एक जज्बा है। इसके संग फलते-फूलते हैं ढेरों किस्से। यह प्रतीक है खुशियों का, जो हर गर्मी नए सिरे से रंग भरता है जीवन में। जब यह छोटा होता है, हरा, तो रहता है शोखियों से भरपूर। तब किसी बच्चे-सा नटखटपन दिखता है इसमें, जो उकसाता है, चिढ़ाता है। लेकिन, पकने के बाद इसी का रस देता है अद्भुत अनुभव, जैसे कोई शीतल हवा शरीर में घुलती जा रही हो। कई और स्वाद भी हैं गर्मियों के, पर वे सिर्फ जुबान पर चढ़ते हैं। आम रास्ता बनाता है सीधे दिल तक। इसका मुलायम रस भरा आनंद किसी और में नहीं।

इस आनंद का इतिहास करीब पांच हजार साल पुराना है और इस आनंद की किस्में लगभग 14 हजार। अकेले भारत में ही डेढ़ हजार से ज्यादा तरह के आम पैदा होते हैं। रटौल, तोतापरी, केसर, हिमसागर, हापुस, बादामी, नीलम - आम के चाहने वाले ही बता सकते हैं कि इनमें से हर एक वैरायटी कितनी खास है और कितनी अनोखी। टॉमी एटकिन्स अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले थॉमस एच एटकिन्स के बागों की उपज है, तो लंगड़ा आम के बारे में कहानी है कि इसे बनारस के एक पुजारी ने तैयार किया था।

सभी की अनूठी खूबी और अमृत-सा स्वाद- लंगड़ा का मीठा, दशहरी का रसीला तो चौसा का खुशबूदार। कोई लाल, कोई पीला, कोई बैंगनी रंग लिए। इसके सम्मोहन में बंधकर ही सागर खय्यामी कह गए, 'आम तेरी ये खुशनसीबी है वर्ना लंगड़ों पे कौन मरता है।' है तो यह आम, लेकिन उठता-बैठता है बादशाहों के बीच। इसने मुगलों का गुरूर तक तोड़ दिया। काबुल घाटी के सफर पर निकले मुगल बादशाह जहांगीर ने वे स्थानीय फल खाए, जिनके बारे में उनके पुरखे बड़ाई पर बड़ाई किया करते थे। लेकिन, जहांगीर को अपने पुरखों की धरती का एक भी स्वाद न जमा।

AI Image

जीवन आनंद

उन्होंने लिखा कि काबुल के फल बेशक लाजवाब हैं, लेकिन आम के मुकाबले कुछ भी नहीं। जहांगीर को बात जरा देर से समझ आई। हिंदुस्तान में ही किसी से पूछ लिया होता उसने तो जवाब मिल जाता कि न कश्चित् आम्रवत् यानी आम जैसा कोई नहीं। कोई चाहकर भी आम की जगह नहीं ले सकता। इसने दुनिया को मैंगो डिप्लोमेसी का गिफ्ट दिया और चीन के कल्चरल रिवॉल्यूशन को मैंगो कल्ट। दबदबा इसने ऐसा कायम किया कि dining etiquette पूरी तरह उलट-पलट गया। इसे खाने का एक ही रूल है, नो रूल। सबसे सरल और प्रिय तरीका है इसे सीधे छीलकर खाना। पीले गूदे पर चाकू पड़ते ही टपकने वाला रस मोह लेता है मन को। फिर हाथों और मुंह का रस से तर हो जाना, यह सबूत है आम के प्रति समर्पण का।

नफासत वाले छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर खाते हैं इसे, जबकि बेसब्र लोगों को पसंद है गुलगुला कर चूसना। अगर आपने कोई और तरीका ईजाद किया है, तो और भी अच्छी बात है। आम के मामले में केवल मंजिल महत्वपूर्ण रह जाती है, रास्ता कोई भी हो सकता है। वैसे आम के बारे में इतनी बतकही की जरूरत नहीं है। बस उठाइए और शुरू हो जाइए। आनंद लीजिए फलों के राजा का और पूरी तरह डूब जाइए उसमें।

शेयर करें अपने अनुभव
जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesgroup.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- **'जीवन आनंद'**

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

माया मकड़जाल की तरह हमें हर पल उलझाती है

आशुतोष महाराज

तनाव से कैसे छुटकारा पाया जाए? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब पाने की जगह आजकल 'स्ट्रेस मैनेजमेंट' पर वर्कशॉप, वेबिनार और व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं। इतने मैनेजमेंट के बावजूद तनाव का ग्राफ तेजी से आसमान छूता जा रहा है। कारण क्या है? आप कभी मकड़जाल पर गौर कीजिएगा। जाल पर मकड़ी फर्राटे से दौड़ती है, पर मक्खी, मच्छर या अन्य कीड़े-मकौड़े उसमें कैद हो जाते हैं। चाहकर भी उस जाल से निकल कर भाग नहीं पाते। बात यह है कि जाल एक तरफ से चिपचिपा होता है और दूसरी तरफ सूखा रहता है। मकड़ी समझदारी से उसी तरफ चलती है, जिधर चिपचिपाहट नहीं होती। बेचारे कीड़े-मकौड़े चिपचिपी वाले हिस्से में फंस जाते हैं। समझना होगा कि मुक्ति अलग चीज होती है और मैनेजमेंट अलग चीज।

इसी तरह से इस माया रूप जगत के भी एक तरफ 'और-और' पाने की चिपचिपाहट है। अफसोस! हमारा मन अधिक से अधिक धन, ऐश्वर्य, और रुतबा चाहता है। इस 'और-और' के जाल में चिपक जाता है। फिर सोच इसी में अटक जाती है- यदि यह 'और' न मिला तो? यह अटकन ही हमें घोर तनाव की भटकन में धकेल देती है। इसलिए धन, वस्तुओं, ऐश्वर्य, पद से इतना लगाव न करें कि उनके न मिलने या छिन जाने पर अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठें, तनावग्रस्त हो जाएं।

इच्छित वस्तु मिले या न मिले, दोनों ही परिस्थितियों में समता रखना हमें अध्यात्म सिखाता है। आइए, वैज्ञानिक शैली में उत्तर जानें। भौतिक विज्ञान के अनुसार तनाव को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- तनाव = दबाव/क्षेत्रफल, यानी जितना दबाव बढ़ेगा, तनाव भी उसी अनुपात से बढ़ता चला जाएगा। वहीं जिस क्षेत्र पर जब दबाव पड़ रहा है, वह बड़ा होता जाएगा, तो तनाव कम होता जाएगा। अक्सर हम मन और दिमाग के स्तर पर ही ऐसी परिस्थितियों से जूझते हैं। और एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं, जब हमारा तन-मन दिमाग जवाब दे जाता है। ऐसे में अध्यात्म हमारे सामने एक ठोस समाधान रखता है।

अध्यात्म का अर्थ होता है 'आत्मा का अध्ययन' यानी आत्मा की साक्षात अनुभूति! चूंकि ईश्वर अनंत है और आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए आत्मा का क्षेत्रफल भी असीम हुआ। इसलिए जब हम आध्यात्मिक साधना द्वारा असीम आत्मिक स्तर से जुड़ जाते हैं, तब दबाव सहन करने का अपना सामर्थ्य भी अनंत हो जाता है। 'तनाव = दबाव/क्षेत्र' के हिसाब से विभाजक (denominator) के अनंत होने पर तनाव लगभग शून्य हो जाता है।

दक्षिण भारत के चिदंबरम मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ा खाली क्षेत्र है। यहां से आगे बढ़ने पर नटराज की मूर्ति सुशोभित है। मंदिर का खाली क्षेत्र हमारे आंतरिक जगत की ओर इशारा है, जो अंबर के समान विशाल है। जब हम मन-बुद्धि के ऊहापोह को पार कर अपने इस अंतर्जगत के क्षेत्र में स्थित हो जाते हैं, तब नितांत शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति हमें नटराज की ओर ले जाती है। नटराज प्रतीक है, जीवंतता का, उत्साह का, ऊर्जा का, प्रसन्नता का। ऐसे में जीवन तनाव से मुक्त आनंद से युक्त हो जाता है।

क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग हुई आसान?

मृत्युंजय राय

क्रिप्टोकरंसी को लेकर कई देश आशंकित हैं। इन देशों में चीन और भारत भी शामिल हैं, जो दुनिया की शीर्ष 5 बड़ी इकॉनमी में से आते हैं। इन देशों को यह डर परेशान करता आया है कि क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे अपराधों के लिए किया जाएगा और ऐसा हो भी रहा है। **'Rinsed'** नाम की किताब में इन्हीं के बारे में बताया गया है। इसे लिखा है ज्यॉफ वाइट ने।

Chainalysis नाम की ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी का अंदाजा है कि पिछले साल ही क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करके कोई 22.2 बिलियन डॉलर की रकम का अवैध लेनदेन हुआ। खासतौर पर इसका इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश कर रहे हैं, जिन पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। यहां तक कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन भी क्रिप्टोकरंसी का प्रयोग अवैध लेनदेन के लिए कर रहे हैं। ज्यॉफ वाइट की मानें तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। वह लिखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा और भी बढ़ने वाला है क्योंकि तकनीक की वजह से इस अपराध को अंजाम देना आसान हो गया है। और यह तो सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए इसी वजह से इस अपराध का पता लगाना मुश्किल हो गया है।

AI Image

विचार विंडो

अगर आपके मन में यह सब पढ़ने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्रिप्टोकरंसी के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है तो उसका जवाब भी ज्यॉफ वाइट ने दिया है। वह किताब में लिखते हैं कि क्रिप्टो के जरिये काले धन को सफेद में बदलने का धंधा तीन चरणों में पूरा होता है। इसमें पहले चरण में काले धन को वित्तीय व्यवस्था में डाला जाता है। यह काम बिचौलियों के जरिये होता है, जो काले धन को बिटकॉइन में बदलते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में जिस शख्स का काला धन होता है, वह सामने नहीं आता।

दूसरे चरण में इस बिटकॉइन को कई खातों में घुमाया जाता है ताकि इसके वास्तविक स्रोत की जानकारी छुपाई जा सके। इसके लिए विदेशी बैंकों और शेल कंपनियों का सहारा लिया जाता है। इस मकाम पर इस पूरे प्रॉसेस में 'मिक्सर्स' की भूमिका भी अहम हो जाती है। ये बिटकॉइन को दूसरी क्रिप्टोकरंसी के साथ मिलाते हैं। उसके बाद ये कस्टमर को उसकी वास्तविक रकम वापस करते हैं। इस प्रक्रिया के आखिरी चरण में इस सफेद धन से संपत्तियां खरीदी जाती हैं। ज्यॉफ वाइट बताते हैं कि क्रिप्टो के इस खेल में शामिल रियल यूजर्स सफेद धन से प्रॉपर्टी जैसे असेट्स खरीदना पसंद करते हैं, जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ सके।

एक तरह से देखिए तो क्रिप्टोकरंसी को लेकर दुनिया के कई देशों में वित्तीय नियामकों को जो आपत्तियां रही हैं, यह किताब उनकी आशंकाएं सही साबित करती है। ये नियामक कहते आ रहे हैं कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग और बढ़ेगी। काले धन का साम्राज्य और बड़ा होगा। भारत में भी नियामकों की ओर से यह आशंका जताई गई थी। हालांकि, यहां क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित नहीं किया गया, लेकिन इसे बढ़ावा न मिले, इसके लिए इस पर भारी टैक्स लगाया गया है।

भारतीय नियामक इस लिहाज से कामयाब भी रहा है कि क्रिप्टोकरंसी को लेकर कुछ साल पहले जो क्रेज था, वह अब आम लोगों में नहीं दिखता। कह सकते हैं कि इसकी पॉप्युलैरिटी कम हुई है। लेकिन यह तो इस मामले का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू यह हो सकता है कि अपराध की दुनिया किस हद तक इसका इस्तेमाल कर रही है। क्या रेगुलेटरी पहल से उस पर भी लगाम लगी है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उन्हें रोकने के लिए जांच एजेंसियों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए?

अच्छा है ये चलन

प्रणव प्रियदर्शी

अपने देश में हम परिवार की खातिर महिलाओं को ही 'एडजस्ट' करते देखने के आदी रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए। आज की तारीख तक यही प्रमुख ट्रेंड रहा है और है, इसका मतलब यह नहीं है कि आगे भी यही स्थिति रहेगी। स्थिति बदलने का संकेत देता है इसका उलटा ट्रेंड जो अभी हावी भले न हुआ हो, दिखने जरूर लगा है। और नया ट्रेंड है पत्नी की जरूरत, उसके करियर को देखते हुए पति के एडजस्ट करने का। यह एडजस्टमेंट सिर्फ घर का काम करने और बच्चों की देखभाल के लिए वक्त निकालने तक सीमित नहीं। इसका मतलब अपने करियर को प्राथमिकता में नीचे रखते हुए पत्नी के करियर की खातिर दूसरे शहर या देश में शिफ्ट होना भी है। इस नए ट्रेंड को लेकर कोई ठोस डेटा तो नहीं है, लेकिन ऐसे उदाहरण हमें अपने आसपास दिखने लगे हैं। कुछ मामले मीडिया में भी आते हैं जब-तब। मिसाल के तौर पर IIT दिल्ली के पूर्व छात्र पीयूष जैन, जिनका स्टार्टअप्स को अडवाइज करने का काम है, एक नहीं दो-दो बार रीलोकेट हो चुके हैं। पहली बार 2010 में, जब वह एक MNC में काम करने वाली अपनी पत्नी श्वेता के डिपेंडेंट के तौर पर अमेरिका गए। वहां से लौटने पर दोनों ने दिल्ली को ठिकाना बनाया। लेकिन 2014 में फिर वह बेंगलुरु शिफ्ट हुए जब श्वेता का ट्रांसफर हुआ। ऐसे ही हरप्रीत सिंह ग्रोवर ने पत्नी को मुंबई में मिले एक अच्छे ऑफर के कारण 2016 में गुरुग्राम स्थित अपना एजुकेशनल स्टार्टअप बेच दिया ताकि दोनों साथ रह सकें। आखिर पत्नी 2010 में ही हॉन्गकॉन्ग का अपना जॉब इसलिए छोड़ चुकी थीं क्योंकि हरप्रीत के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। एक्स नेवी ऑफिसर अमन चावला कॉरपोरेट जॉब में जाना चाहते थे, लेकिन पत्नी को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन मिला तो उसका यह मौका हाथ से निकल न जाए यह सोचकर उनके साथ कनाडा चले गए। ये उदाहरण अभी भले इक्का दुक्का हों, वक्त के बदलने का संदेश तो दे ही रहे हैं।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

चेक बुक का महत्व
17 जून को 'जीवन आनंद' कॉलम में प्रकाशित लेख 'कद ही नहीं, आपकी खुशियों का पैमाना भी है चेक' पढ़ा। लोग पहले लेन-देन कैश में करते थे। अब अधिकतर लेन-देन UPI के जरिए करने लगे हैं। रजिस्ट्री करानी हो, एग्जाम फी भरनी हो तब जरूर चेक या डीडी की जरूरत पड़ती है। पहले जब सैलरी चेक में मिलती थी, अब तो अमाउंट डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए वह अहसास नहीं मिलता। हालांकि किसी भी विधि से आए, अकाउंट में पैसे आना खुशी देता ही है, लेकिन चेक बुक पर अमाउंट भरने और उस पर सिग्नेचर करने का आनंद ही कुछ और होता है।
कृतिका झा, ईमेल से

आगे बढ़ने की ताकत
यह पत्र 17 जून को प्रकाशित लेख 'कद ही नहीं, आपकी खुशियों का पैमाना भी है चेक' से संबंधित है। चेक बुक पर अमाउंट भरना एक खास अनुभव होता है। चेक बुक में अमाउंट भरते हैं, तो हमें उसके पीछे छिपी अपनी मेहनत और समर्पण का एहसास होता है। आखिर खाते में वह राशि यूं ही नहीं आई होती है। उससे हमारी आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा भी जुड़ी है। अमाउंट भरते समय हमें यह महसूस होता है कि हमारे खाते में जो धनराशि है, वह भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने की ताकत है।
जितेंद्र यादव, शाहदरा

जीवन आनंद

आईना सच बोलता है
'सच दिखाने वाला आपका पक्का दोस्त है आईना' जीवन आनंद कॉलम में 3 जून को प्रकाशित यह लेख पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। आईना हमें अपने आप से साक्षात्कार करने का अवसर देता है। जब हम आईने में खुद को देखते हैं, तो हमें अपनी शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और व्यक्तित्व प्रस्तुति का अंदाजा मिलता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने रूप-रंग को सुधारने में हमारी मदद करता है। पहनावे को बेहतर बना सकते हैं।
प्रतीक गुप्ता, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र
राहुल गांधी या कोई और, नेता प्रतिपक्ष पर अभी फैसला नहीं- खबर।
- क्या जिम्मेदारी लिए बगैर राजनीति बदलना चाहते हैं?
राजेंद्र भटनागर

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु. संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी)

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

शांति व एकता का प्रयास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना कर शांति व एकता स्थापित करने में योग की भूमिका पर जोर दिया। 21 जून, 2024 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को उस समय नए अर्थ मिल गए जब प्रधानमंत्री ने इसे कश्मीर में मनाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुंदर कश्मीर घाटी में मना कर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बना दिया। यह आयोजन न केवल वैश्विक आयोजन के तौर पर योग का महत्व स्थापित करता है, बल्कि यह ऐसे क्षेत्र में शांति, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जहां टकराव और तनाव व्याप्त रहा है। अक्सर अपनी सुंदर दृश्यावलियों तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए चुना। यह आयोजन श्रीनगर के प्रख्यात शालीमार बाग में हुआ। हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस की स्थापना 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रस्ताव स्वीकृति से हुई थी। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में रखा था। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में योग करने के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह परंपरा भारत में 5,000 साल पहले पैदा हुई थी। इसमें शरीर, मन और आत्मा के बीच समन्वय पर जोर दिया जाता है जिससे एक संतुलित व सामंजस्यपूर्ण जीवनशैली विकसित होती है। इस वर्ष की थीम 'योग स्वयं व समाज के लिए' कश्मीर में अत्यधिक सार्थक है क्योंकि यह क्षेत्र जटिल सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।

कश्मीर में योग दिवस मना कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शांतिपूर्ण भविष्य के लिए सुलह-समझौते की भावना और उसकी क्षमता का संदेश दिया। वास्तव में प्रधानमंत्री हमेशा प्रतीकों का बहुत प्रभावी प्रयोग कर लोगों को संदेश प्रसारित करते रहते हैं और कश्मीर में योग दिवस मनाना भी इसका कोई अपवाद नहीं था। एक स्थल के रूप में इसके लिए कश्मीर का चयन अनेक प्रतीकों से भरा है। यह क्षेत्र दशकों से टकराव और अशांति का सामना कर रहा है, ऐसे में आयोजन के लिए जनता का भारी समर्थन शांति एवं सामान्य स्थिति बहाली की उनकी इच्छा प्रकट करता है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति तथा निवासियों की जोशीली सहभागिता घावों पर मलहम लगाने तथा विभाजन समाप्त करने की दिशा में एक कदम है। यह लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने के बाद इस संघशासित क्षेत्र की प्रधानमंत्री मोदी की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की नींव रखी और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2024 की गतिविधियों में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी या उनका लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने स्वास्थ्य और एकता को प्रोत्साहित करने में योग का महत्व रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सीमापार भी एक कड़ा संदेश भेजा कि आतंकवाद के सभी कृत्यों को विफल किया जाएगा। वास्तव में उनकी इस यात्रा से जनता में विश्वास बढ़ेगा जो जम्मू में आतंकी हमलों के कुछ ही सप्ताह के भीतर हुई है। यह सुरक्षा बलों को भी संदेश है कि वे सुरक्षा व्यवस्थाओं में तेजी लाएं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने जम्मू कश्मीर में विकास एवं एकजुटता के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है। वास्तव में यह आयोजन केवल योगाभ्यासों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर राज्य में बेहतरी और एकता की भावना प्रोत्साहित करने का सुनियोजित प्रयास भी था।

नीट परीक्षा में गंभीर विकृति

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 'नीट' परीक्षा में कमियों को गंभीरतापूर्वक संबोधित करने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा प्रणाली की एक गंभीर विफलता है।

सिद्धार्थ मिश्रा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 'नीट' परीक्षा में कमियों को गंभीरतापूर्वक संबोधित करने का निर्देश दिया है। यह गंभीर विफलता है। योजनायें कई बार पटरी से उतर जाती हैं। यह बात एक सीमा तक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बारे में कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सुशासन के असाधारण मानक स्थापित करने की योजना बनाई थी। लेकिन फिलहाल यह सफल होती नहीं लग रही है। पहले तो लोकसभा में भाजपा सदस्यों को इच्छित संख्या में भारी बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण शायद सरकार की सक्रियता में थोड़ी कमी आई। इससे भी बुरी बात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी-'एनटीए' द्वारा नेशनल इलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट 'नीट' के घोषित परिणाम में नंबरों को लेकर विवाद से पैदा हुई। यह देश भर में सभी मेडिकल कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जून को केन्द्र सरकार और एनटीए से यह सुनिश्चित करने को कहा कि यदि नीट-यूजी, 2024 परीक्षाओं में 0.01 प्रतिशत भी लापरवाही पाई गई हो तो उसे इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि छात्र इस राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए अत्यधिक परिश्रम करते हैं। सौभाग्य से धर्मेन्द्र प्रधान जैसे परिपक्व नेता देश के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री हैं। उनसे आशा है कि वे इस संकट से पूरी गंभीरता से निपटेंगे तथा शिक्षा मंत्रालय के मुख्यालय शास्त्री भवन में रहे अपने पूर्ववर्तियों स्मृति ईरानी या रमेश पोखरियाल निशंक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब तक धर्मेन्द्र प्रधान ने इस गंभीर संकट से निपटने में पूरे धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया है। 'नीट' परीक्षा को लेकर पैदा अव्यवस्था बहुत गंभीर है। यह परीक्षायें कराने में कथित विसंगतियों तथा नंबर देने में हेराफेरी से आगे तक जाती है। मेडिकल कालेजों में सीमित संख्या में सीटें होने के कारण यह अत्यधिक गंभीर वित्तीय तथा भावनात्मक मामलों का मामला भी है। हर साल 'नीट' परीक्षा में 15 लाख से अधिक छात्र भाग लेते हैं जो चिकित्सा विश्वविद्यालयों में उपलब्ध लगभग 83,000 सीटों पर प्रवेश का प्रयास करते हैं। इन सीटों में आधी से अधिक विभिन्न प्रकार से 'आरक्षित' होती हैं। इस प्रकार सीटें कम होने तथा आरक्षित सीटों के कारण उनकी संख्या और कम होने से बहुत से योग्य छात्र सरकारी कालेजों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। भारत के निजी मेडिकल कालेजों में फीस अविश्वसनीय रूप से बहुत अधिक है। ये बहुत खर्चीले हैं और इनमें पूरे पाठ्यक्रम के लिए फीस लगभग एक करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बच्चों को डाक्टर बनाने हेतु इतना खर्च उठाना अकल्पनीय है। इसी कारण अनेक मध्यवर्गीय छात्र विदेशों में सस्ती चिकित्सा शिक्षा का विकल्प अपनाते हैं।

हालांकि, विदेशों के अनेक मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षा का स्तर भारतीय स्तर से कमतर होता है। भारत में चिकित्सा शिक्षा महंगी होने तथा सरकारी कालेजों में समुचित सीटें न होने के कारण चीन, यूक्रेन, रूस और किर्गिजिस्तान जैसे देशों में 'मेडिकल कालेज बाजार' खुल गए हैं। यहां चिकित्सा शिक्षा पर खर्च भारतीय निजी मेडिकल कालेजों पर होने वाले खर्च की तुलना में लगभग आधा है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि चीन में कोविड, मध्य एशिया में युद्ध तथा किर्गिजिस्तान में गुंडागर्दी के कारण वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की परेशानियां अक्सर मीडिया सुर्खियों में स्थान पाती हैं। छात्रों की समस्यायें केवल इतने पर ही समाप्त नहीं होती हैं। सफलतापूर्वक चिकित्सा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी अक्सर उनको अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है। विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त चिकित्सा डिग्रियों की नेशनल मेडिकल कमीशन आफ इंडिया-एनएमसीआई से मान्यता जरूरी होती है। यदि विदेश में स्थित मेडिकल कालेज को मान्यता प्राप्त हो तो भी वहां से चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए एनएमसीआई द्वारा कराई फारेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इक्जामिनेशन-एफएमजीई पास करना पड़ता है। यह भी तथ्य है कि एफएमजीई परीक्षा पास करने वाले छात्रों की दर तुलनात्मक रूप से कम है।

इस प्रकार भारतीय चिकित्सा शिक्षा में सीटों की कमी से बार-बार भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते रहे हैं। पिछले अनेक सालों से चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस स्थिति के अनेक भीषण परिणाम सामने आते हैं। इसका सबसे गंभीर परिणाम चिकित्सा शिक्षा पर भारी खर्च, प्रवेश के लिए प्रतीक्षा का लंबा समय तथा सीमित संसाधनों के कारण बहुती प्रतियोगिता है। सीटों की कमी के कारण ऐसा परिवेश बनता है जिसमें विभिन्न लोग या हितधारक सीमित संसाधनों तक पहुंच के लिए रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं ताकि उनको किसी न किसी प्रकार सरकारी मेडिकल कालेजों में प्रवेश मिल सके। आज 'नीट' के परिस्थितिकी-तंत्र में केवल छात्र और परीक्षा एजेंसियां ही शामिल नहीं हैं। सुरक्षित रूप से यह भी कहा जा सकता है कि इस परीक्षा में बड़ी मात्रा में वित्तीय दांव लगे होते हैं।

इस व्यवस्था में अनेक कोचिंग सेंटरों और प्रवेश कौंसिलरों के साथ स्वयं छात्र भी वित्तीय रूप से अपना बहुत कुछ दांव पर लगा देते हैं। इसके साथ ही अनेक लोग इस काम में भी लगे रहते हैं कि व्यवस्था में तोड़-मरोड़ कर भारतीय सरकारी मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश को 'सुविधाजनक' बनाया जाए। सरकारी मेडिकल कालेजों में प्रवेश न मिलने पर छात्रों के परिवारों को अपने परिवार की संचित पूंजी लगा कर या तो बच्चों को निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिलाना पड़ता है या उनको डाक्टर बनाने के लिए विदेशी मेडिकल कालेजों में भेजना पड़ता है। लेकिन विदेशी मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है। उनको संबंधित देशों में विभिन्न समस्याओं का सामना करने के बाद चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पास करने पर भारत में डाक्टरी करने के लिए एफएमजीई परीक्षा पास करनी पड़ती है। विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनेक छात्र इस परीक्षा में विफल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशों में वे भारतीयों को होने वाली बीमारियों और उनके इलाज से परिचित नहीं होते हैं। इसलिए भारत में पढ़े और प्रशिक्षित डाक्टरों की तुलना में उनकी क्षमता कम हो सकती है।

ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से उम्मीद है कि वे तत्कालीन संकट में राहत प्रदान करने के साथ ही उन लाखों छात्रों को सांत्वना दें जो एनटीए द्वारा आयोजित नीट, 2004 में शामिल हुए थे। दूरगामी राहत केवल स्वास्थ्य ढांचागत क्षेत्र में भारी निवेश से ही संभव है। सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों व खासकर सरकारी कालेजों में सीटें बढ़ाने से छात्रों को विदेशों में डाक्टरी पढ़ने या 'भ्रष्टाचारी' तत्वों के हाथों में खेलने से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए चिकित्सा विज्ञान की ढांचागत संरचना तथा चिकित्सा शिक्षकों के प्रशिक्षण में काफी निवेश करने की जरूरत है।

यह काम केवल शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान या नव-नियुक्त स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा की पहल से ही संभव नहीं होगा। इसके लिए सरकार के समुचित दृष्टिकोण तथा महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी ताकि वह निजी मेडिकल कालेजों द्वारा चलाए जा रहे 'कार्टेल' की तोड़ सके। इन निजी मेडिकल कालेजों के प्रबंधन ने चिकित्सा शिक्षा पर अपनी 'आक्टोपस जैसी' जकड़ बना रखी है। निजी मेडिकल कालेजों के लिए कोचिंग सेंटर तथा कौंसिलर भी एक प्रकार से औजार का काम करते हैं। देश में चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश की 'महंगी' प्रक्रिया पर सबसे पहले प्रहार करने की जरूरत है। इस पर विस्तृत विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह मध्यवर्गीय, गरीब व ग्रामीण परिवारों के प्रतिभाशाली नौजवानों को डाक्टर बनने से रोकती है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश, उसके बाद पढ़ाई तथा पारस्नातक पढ़ाई की मजबूरी आम लोगों के लिए भी दवा-इलाज को बहुत महंगा बना देती है। इस प्रकार 'नीट' परीक्षा में विकृति के दूरगामी प्रभाव सामने आते हैं।

आक्रोश के प्रबंधन की कला

> क्रोध या आवेश एक ऐसी भावना है जो हमेशा प्रतिकूल परिणामों की ओर ले जाने का कारण बनती है।

रवि वल्लूरी
(लेखक, रेलवे विभाग से संबद्ध हैं)

बहुत समय पहले एक बुद्धिमान शिक्षक रहते थे, जिन्होंने अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करते समय अपने शिक्षण के हिस्से के रूप में असामान्य तकनीकों को अपनाया। एक दिन उन्होंने अपने छात्रों को एक खाली जार और कंकड़ से भरा एक थैला दिया।

उन्होंने उन्हें जार में जितने हो सके उतने कंकड़ भरने के लिए कहा। छात्र कंकड़ को जार में डालने के लिए संघर्ष करते हुए परेशान हो गए, लेकिन आखिरकार उन्हें डालने में कामयाब रहे।

इसके बाद, शिक्षक ने उन्हें रेत का एक थैला दिया और उन्हें जार में डालने के लिए निर्देशित किया। रेत ने पत्थरों के बीच की सभी जगहों को भर दिया। आखिरकार, शिक्षक ने उन्हें पानी का एक घड़ा दिया और छात्रों से इसे जार में डालने के लिए कहा, जिससे सभी शेष जगहें भर गईं। तब यह घोषित किया गया कि जार हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और कंकड़, रेत और पानी उस चीज का प्रतीक हैं जिसके साथ हम रहते हैं।

शिक्षक ने आगे कहा, अगर हम अपने जीवन को क्रोध (कंकड़ द्वारा दर्शाया गया) से भर देते हैं, तो किसी और चीज़ के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण चीजों (रेत और पानी द्वारा दर्शाए गए) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम खुशी और संतुलन की स्थिति पा सकते हैं।

छात्रों के बीच एक लड़का रहता था जो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। वह हर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। एक दिन, बुद्धिमान शिक्षक ने उसे कीलों का एक थैला दिया और उससे कहा, जब भी तुम नाराज़ हो, उस सामने की दीवार में एक कील ठोक देना। और इस तरह गतिविधि शुरू हुई। पहले दिन, लड़के ने 50 कीलें ठोक दीं। अगले दिन, उसने 40 कीलें ठोक दीं। हर बार जब वह दीवार के पास जाता, तो उसे गुस्सा आने का पछतावा होता। दीवार की ईंटों में कील ठोकना काफी चुनौती भरा था! धीरे-धीरे, उस युवा को पता चला कि दीवार में अनगिनत कीलें ठोकने की तुलना में अपने गुस्से को नियंत्रित करना आसान था। यह तंदुरुस्त युवा पहले से ही इस बेकार की हरकत को करने वाले अपने बैचमेट्स के बीच हंसी का पात्र बन चुका था। समय के साथ, ठोक दी गई कीलों की संख्या बहुत कम होने लगी, जिससे छात्र और उसके दोस्त हैरान रह गए। आखिरकार, एक दिन ऐसा आया जब वह क्रोधित नहीं हुआ और इस तथ्य से खुश हुआ। समझदार शिक्षक ने छात्र को एक और काम सौंपा, अगर तुम पूरे दिन क्रोधित नहीं होते, तो दीवार से एक कील निकाल दो। कई दिनों के बाद, जब दीवार से सभी कीलें निकाल दी गईं, तो भौंहें तन गईं।

आखिरकार, शिक्षक छात्र को दीवार के पास ले गया और उससे पूछा कि उसने क्या देखा। छात्र ने जवाब दिया कि वह दीवार में छेद देख सकता है। ये छेद उस निशान की तरह हैं जो किसी व्यक्ति के गुस्से में आने पर उसके शरीर पर रह जाते हैं। चाहे आप कितनी भी बार माफ़ी मांग लें, निशान मिटते नहीं हैं।

इसलिए, मैं तुम्हें दो काम करने का सुझाव देता हूँ; यह समझो कि एक बार बोले गए शब्द हमेशा याद रहते हैं। तुम्हारा चिड़चिड़ापन दूसरों को दुख पहुँचाता है और सभी को निराश करता है। उसने आगे कहा, हर बार जब तुम क्रोधित महसूस करो, तो दीवार में 'कील ठोक दो'। सबसे आसान काम जो तुम कर सकते हो, वह है एक पॉकेट डायरी रखना और हर बार जब तुम नाराज़ होओ, तो एक रेखा खींचना। रात में, उस दिन खींची गई रेखाओं की संख्या गिनना। अगर आप इसे आदत बना लें, तो हर बार जब आप तर्तीया बनेंगे, तो आपको इसे नोट करने की याद दिलाई जाएगी।

एक बार जब आप इस नियम का पालन करेंगे, तो आप जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें होने वाले नुकसान के बारे में आपकी जागरूकता और स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी। छात्र ने अपने शिक्षक द्वारा दी गई इस सरल शिक्षा के माध्यम से अपना सबक सीख लिया था।

आप की बात

कश्मीर से वादा

अपने तीसरे कार्यकाल के पहले कश्मीर दौरे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। उनका कश्मीर से किया यह वादा बहुत पुराना है जो अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के सुधरते हुए हालातों को देखते हुए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा शीघ्र दिया जाना चाहिए ताकि वहां के विकास कार्य तेजी से संभव हो और पूर्ण राज्य होने से वहां के लोगों को अधिक सुरक्षा का एहसास हो। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से विश्व को भी एक सकारात्मक संकेत जाएगा। इसके पहले कश्मीर को सीमापार से होने वाले आतंकी हमलों और घुसपैठ से पूर्ण मुक्ति दिलाना जरूरी है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी सुविधाओं से सेना को लैस करके कश्मीर को आतंकवादियों से पूर्ण मुक्त करवाया जाना अत्यावश्यक है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर का पर्यटन उद्योग अपने पूरे शबाब पर है। प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर में योग दिवस मनाना नरेन्द्र मोदी के दृढ़ आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह आतंकवादियों और सीमापार बैठे उनके आकाओं को चेतावनी भी है कि अब वे कश्मीर में फिर से अपनी जड़ें नहीं जमा पाएंगे। यह अनेक कश्मीरी नेताओं के लिए भी सबक है।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

मोदी की कश्मीर यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान कहा कि प्रदेश में अब शीघ्र ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। निकट भविष्य में केंद्रशासित प्रदेश के राज्य का दर्जा बहाल करने की भी योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली कश्मीर यात्रा के दौरान उम्मीद जताई कि हर क्षेत्र की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी विधानसभा चुनाव में अपने लिए सक्षम प्रतिनिधियों का चुनाव कर उनके जरिए अपनी परेशानियों का हल भी करवा सकेंगे। वैसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 370 समाप्त करने को सही ठहराते हुए जम्मू कश्मीर में सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालय के उसी निर्देश का पालन करने जा रही है। ये विधानसभा चुनाव धारा 370 बहाल होने के बाद यह पहले चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में कश्मीर के लोगों ने 35 साल पुराना मतदान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे देश ही नहीं विदेश में भी एक संदेश गया है कि अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत के साथ एकजुट हो गया है और वहां पुराने अंधकारमय दिन अाने की संभावना तथा आशंका लगभग समाप्त हो गई है।

- मनमोहन राजावत, शाजापुर

हिंदुजा परिवार को सजा

स्विट्जरलैंड की अदालत ने 79 वर्षीय उद्योगपति प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल, बेटे अजय और बहू नम्रता को कमज़ोर एवं भारतीय मूल के घरेलू कामगारों का शोषण करने के लिए हाल में चार से साढ़े चार साल तक कैद की सज़ा सुनाई। हिंदुजा परिवार पर श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त करने, उन्हें विवस फ्रैंक के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान करने, उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने और स्विट्जरलैंड में न्यूनतम वेतन पर अत्यधिक लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। जिनेवा के अभियोजकों ने शोषण, मानव तस्करी और स्विस श्रम कानूनों के उल्लंघन सहित कथित अवैध गतिविधियों की जांच कर ये आरोप लगाए थे। कामगारों को न्यूनतम वेतन 90 डॉलर बदले सिर्फ 9 डॉलर रोज भारतीय रूपए में उनके बैंक खातों में डाला जाता था। इन कामगारों को बंधुआ मजदूरों से बदतर हालात में रखा गया था यहाँ तक कि उस आलीशान घर में कूत्तों की स्थिति भी इन मजदूरों से काफी अच्छी थी। हिंदुजा परिवार को सजा देकर स्विट्जरलैंड की अदालत ने दिखा दिया है कि उनके देश में कानून सबके लिए समान है। कानून और न्यायपालिका की यह निष्पक्षता और गरिमा निश्चित रूप से आदर्श है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

गर्मी का कहर

बरसात की प्रतीक्षा के बीच गर्मी का कहर का जारी है। देश भर में 110 दिन में 100 से अधिक लोगों की जीवन लीला लू से समाप्त हो गई। इस साल 1 मार्च से 18 जून तक 40984 लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हुए थे। गर्मी का यह कहर जानलेवा साबित हो रहा है। इस परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित करना एक चुनौती बन गया। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कारगर कदम उठाना जरूरी है। जनमानस ने बचाव के तहत हाथ मुंह पर अंगौछा या दुपट्टा लपेटने, छाता लगाने के साथ ही अनेक उपाय किए हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है, पर इसके बाद फिर उमस बढ़ जाती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साथ ही स्थानीय निकायों को भी इस भयानक गर्मी के कहर से सबक लेकर नगर-नियोजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन तुरन्त लागू करने चाहिए। आशंका है कि आने वाले वर्षों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा तथा इससे होने वाली जनहानि एवं आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए सभी स्तरों पर उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

- योगेश जोशी, बड़वाह

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 110

बुनियादी बातों का रहे ध्यान

अठारहवीं लोक सभा का पहला सत्र आज शुरू हो रहा है और यह इस बात के लिए सटीक अवसर है कि भारतीय संसद के संचालन की कमियों को दूर किया जाए। नई लोक सभा की पिछली दो लोक सभाओं से अलग माना जा रहा है क्योंकि उन अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। हालांकि इस बार भी भाजपानीत केंद्र सरकार को बहुमत हासिल है लेकिन उसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन लेना पड़ा है। विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी उसे उनकी मदद की आवश्यकता होगी। इसके अलावा विपक्ष के पास भी इस बार अच्छी खासी सीटें हैं। अगर विपक्ष चुनाव पूर्व हुए गठबंधन को बरकरार रखने में कामयाब रहता है तो वह सरकारी नीतियों को लेकर महत्त्वपूर्ण सवाल खड़े करने की स्थिति में होगा। जाहिर है यह संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। 10 वर्ष बाद सदन में विपक्ष का औपचारिक नेता भी मौजूद होगा।

अनुमानों को रेखांकित करने के लिए यह उपयोगी होगा कि हम इस बात पर नजर डालें कि हाल के वर्षों में संसद का कामकाज किस प्रकार चला है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक 17वीं लोक सभा ने अपने निर्धारित समय में से 88 फीसदी काम किया। बहरहाल, सदन की बैठकों के औसत वार्षिक दिवसों की संख्या में अहम कमी आई। लोक सभा की औसतन हर वर्ष 55 दिन कार्यवाही चली जबकि 16वीं लोकसभा में यह औसत 66 दिन था। तुलनात्मक रूप से देखें तो पहली लोक सभा में यह अवधि 135 दिन की थी। हालांकि महामारी ने इन सालाना औसत दिनों की तादाद कम की है लेकिन 15 सत्रों में से 11 को जल्दी समाप्त करना पड़ा। कार्य दिवसों की इस कमी ने सदन के कामकाज पर गहरा असर डाला। करीब 35 फीसदी विधेयक एक घंटे से भी कम अवधि में पारित कर दिए गए। ध्यान देने वाली बात है कि 17वीं लोक सभा के दौरान दोनों सदनों के सदस्यों को निलंबित करने की 206 घटनाएं घटीं। 2023 के शीतकालीन सत्र में 146 सदस्यों को कदाचरण के कारण निलंबित किया गया।

हालिया प्रदर्शन को देखते हुए यह उम्मीद करना उचित ही है कि 18वीं लोक सभा में मौजूदा रुझान बदलेगा। सदन के सुचारु संचालन की जिम्मेदारी जहां सत्तारूढ़ पक्ष की है, वहीं विपक्ष से भी उम्मीद की जाती है कि वह सकारात्मक भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सत्तारूढ़ पक्ष को भी कम से कम दो मोर्चों पर सुधार करने की आवश्यकता है। पहला लोक सभा या दोनों सदनों में एक वर्ष के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ानी होगी। इससे सदस्यों को प्रासंगिक मसले उठाने का अवसर मिलेगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सकेगा। दूसरा, विधेयकों को बिना समुचित चर्चा के पारित नहीं किया जाना चाहिए। संसदीय व्यवस्था में सरकार हमेशा बहुमत रखती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के पारित हो जाएं। सरकार को विपक्ष को यह अवसर देना ही चाहिए कि वह हर मुद्दे पर अपनी राय रखे।

इसके अलावा 17वीं लोक सभा में 20 फीसदी से भी कम विधेयकों को समितियों के पास भेजा गया जबकि 15वीं लोक सभा में 71 फीसदी विधेयक समितियों को सौंपे गए थे। संसदीय समितियां विधेयकों के आकलन की सटीक व्यवस्था हैं जो सभी संबद्ध पक्षों के बीच के मतभेद समाप्त करने का काम करती हैं। यह व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल की जानी चाहिए। इससे सरकार को व्यापक चर्चा का अवसर मिलेगा। खासतौर पर संवेदनशील मसलों पर। चर्चा और सहमति बनाना किसी विचार की राजनीतिक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि नए लोक सभा अध्यक्ष, सरकार और विपक्ष मिलकर सदन में व्यवधान और स्थगन को कम करने का प्रयास करेंगे।

अजय मोहंती

मोदी के तीसरे कार्यकाल में सशर्त होगा शासन

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बदली हुई हकीकत यह है कि हम उस पुराने सामान्य दौर में लौट आए हैं जहां बहुमत होने के बाद भी लगातार बगावतों का सामना करना पड़ता था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 साल से सत्ता में हैं (इनमें से 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में) और पहली बार उन्हें ऐसे माहौल में सरकार चलानी पड़ रही है जहां उनके सामने निरंतर संघर्ष से भरी राजनीति होगी।

जिस मंच पर सबसे तीखा मुकाबला होगा वह है 18वीं लोक सभा जो इस सप्ताह आरंभ हो रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहज बहुमत के बावजूद उत्साहित और एकजुट विपक्ष के 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों की संख्या तकरीबन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों के आसपास ही है।

मोदी तथा उनके नेतृत्व में भाजपा को कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा है। न तो गुजरात में और न ही नई दिल्ली में। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का तरीका रहा है विपक्षी सांसदों को चुप कराने का, उन्हें निलंबित करने का या सदन से निकालने का। गत दिसंबर में 146 सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया था। अब शायद वह ऐसा नहीं कर सके।

विपक्ष मुक्त संसद में कुछ अहम कानून लगभग सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित हुए थे। अपराधों से जुड़े तीन नए कानून इसका सबसे अहम उदाहरण हैं। वे 1 जुलाई से प्रभावी हो रहे हैं। ऐसे में अब सभी विधेयकों पर खुलकर चर्चा करनी होगी और उनका मत परीक्षण भी करना होगा। जिन मामलों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ मजदूर संघों वाले 'साझा हितों' को आधार बनाकर सर्वसम्मति हासिल की गई थी (मसलन न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून) उनको भी अब चुनौती दी जा सकती है। संसदीय समितियों का स्वरूप भी बदल जाएगा। ऐसे में यह आसानी से समझा जा सकता है कि नए लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का यह आकलन गलत साबित हुआ कि भाजपा को आसानी से और बड़ा बहुमत हासिल होगा लेकिन उन्होंने जिस दूसरे बदलाव की बात कही थी वह सही प्रतीत हो रहा है क्योंकि उनका पहला अनुमान गलत है। उन्होंने कहा था कि बड़े बहुमत के बाद भी भाजपा को असहमति और विपक्ष का सामना करना होगा। जहां तक उनके तीसरे पूर्वानुमान का प्रश्न है तो ब्रांड मोदी में गिरावट आ रही है। यहां पुराने जुमले का इस्तेमाल करते हुए कहा जा सकता है कि यह तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा।

विपक्ष पहले ही तीन मुद्दों पर अपनी धार तेज कर रहा है: लगातार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना, अग्निपथ योजना और मणिपुर। तीनों मुद्दे ऐसे विशाल मतदाता वर्ग से जुड़े हैं जो भाजपा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों पेपर लीक पर संवाददाता सम्मेलन करके पहली चाल चल दी है। उन्होंने अग्निपथ योजना का नाम भी लिया। सरकार चुनाव के पहले ही अग्निपथ योजना की समीक्षा कर रही थी लेकिन अब उसे दो बातें समझनी होंगी। पहली, विपक्ष किसी प्रकार के बदलाव के लिए राजी नहीं होने वाला है, वह पूरी योजना को रद्द कराना चाहता है। दूसरा, अगर सरकार कुछ अहम बदलावों के साथ इसे जारी भी रखना चाहती है तो विपक्ष दावा करेगा कि उसने सरकार को विवश किया। 17वीं लोक सभा में जब मोदी सरकार की चिरपरिचित गोपनीय और चौंकाऊ शैली में यह योजना लागू की गई थी तब ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था।

परीक्षा लीक की बात करें तो संबंधित मंत्री पहले ही जिम्मेदारी लेकर समीक्षा और जांच की घोषणा कर चुके हैं। मणिपुर में सामान्य हालात बहाल करने में नाकामी के बावजूद भाजपा को अब तक मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा है। अब जबकि राज्य की दोनों सीटों पर कांग्रेस के सांसद हैं और मुख्यमंत्री वीरेन सिंह की विश्वसनीयता को भी तगड़ी क्षति पहुंची है, मोदी सरकार भी वहां के हालात को लेकर पहले की तरह आंखें नहीं मूंद रह सकती।

अब राज्य सभा में भी एक नई चुनौती होगी, हालांकि वह लोक सभा की तरह गंभीर नहीं होगी। अब तक भाजपा को दो अहम क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल था, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और ओडिशा में बीजू जनता दल। इसमें महत्त्वपूर्ण और विवादित विधेयकों पर समर्थन भी हासिल था, उदाहरण के लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को संवैधानिक रूप से करने का प्रयास।

दोनों ही दल न तो राजग के सदस्य थे और न ही औपचारिक रूप से किसी तरह भाजपा के सहयोगी थे। भाजपा ने दोनों के राज्यों में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था लेकिन दोस्ताना ढंग से। दोनों ही बहुमत वाली सरकार के आज्ञाकारी विपक्ष की भूमिका में थे। क्या अब भाजपा उनके अंध समर्थन की अपेक्षा कर सकती है। दोनों दलों को विधानसभा चुनावों में भाजपा या उसके सहयोगी दल के हाथों हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में उन राज्यों में राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। अंत में संसद के भीतर अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार कर लेते हैं तो उनके पास यह संवैधानिक अधिकार होगा कि अहम पदों पर नियुक्तियों के लिए वह प्रधानमंत्री के साथ बैठें। इनमें केंद्रीय जांच ब्यूरो तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख और निर्वाचन आयोग के मुखिया के पद शामिल हैं। यदाकदा ही सही उन्हें राहुल के साथ नजर आना होगा और यह प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी तब्दीली होगी। मोदी सरकार के लिए तीसरी पारी में एक बदलाव यह भी होगा कि पुराने सामान्य दिनों की वापसी होगी जहां बहुमत वाले दल को भी नियमित रूप से असंख्य बगावतों से निपटना पड़ता था। पिछला एक दशक केंद्र सरकार के लिए सबसे कम चुनौतीपूर्ण समय था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उभरे विरोध प्रदर्शनों को आसानी से दबा दिया गया। केवल किसान आंदोलन को जीत मिली। मोटे तौर पर सरकार को यह सुविधा थी कि वह चुनौतियों को अलग-अलग खाकों में बांट सके और उनसे निपटे तथा कुछ को टाल सके। ये चुनौतियां बहुत बड़ी नहीं हैं लेकिन ये दिखाती हैं कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार को अब भारत के शासन के दौरान उभरने वाली भिन्न-भिन्न चुनौतियों से भी निपटना होगा। उदाहरण के लिए पंजाब और कश्मीर में चुनाव जीतने वाले तीन कट्टरपंथियों की बात करें तो उनमें से दो अभी भी जेल में हैं। इससे पहले मोदी का सामना ऐसी किसी परिस्थिति से नहीं हुआ था।

अंत में बात करते हैं उन राजनीतिक चुनौतियों की जो चुनाव नतीजे आने के बाद सामने आई हैं। सन 2002 में जब मोदी ने गुजरात में पहली बार अपनी पार्टी को जीत दिलाई थी। तब भी उनकी चुनाव जीतने की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं था। उसके बाद हर चुनाव ने उनकी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वोट जुटाने वाले सबसे प्रमुख नेता का कद अर्जित किया। बाद में वह ऐसा करने वाले इकलौते नेता रह गए। हाल में भाजपा-आरएसएस की विचारधारा का विरोध करने वाले कई नेता यह सोचकर भाजपा में शामिल हो गए कि 'मोदी की गारंटी' चुनाव जीतने में उनकी मदद करेगी। क्या यह धारणा अब भी है?

वर्ष 2014 और 2019 के आम चुनावों के बाद यह भी स्पष्ट हो गया था कि आम चुनाव के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में से कई में मोदी अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके थे। तब कहा गया था कि जब उनके नाम पर वोट मांगा जाता है तब जीत मिल जाती है लेकिन विधानसभा चुनावों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वे अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इसे नाकामी नहीं माना गया क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बढ़ रहा था। अब पहले महाराष्ट्र में उसके बाद हरियाणा और फिर झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले वर्ष जनवरी में दिल्ली और सितंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों पर उनके चाहने वाले और विरोधियों दोनों की नजर होगी।

ऐसा नहीं है कि अतीत में मोदी के सामने चुनौतियां नहीं आईं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने तथा उनके प्रमुख सहायकों ने कई मामलों और जांच का सामना किया। यहां तक कि पश्चिम के देशों ने उनका बहिष्कार तक किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कीं। हालांकि इससे कमजोर होने के बजाय उनकी राजनीति मजबूत हुई। ऐसा इसलिए कि वह अपनी विचारधारा के लिए लड़ रहे थे और उनका जनाधार प्रसन्न था। चुनाव में कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सका। वर्तमान हालात इससे अलग हैं।

विनिवेश लक्ष्य पर भारी पड़ता नीतिगत बदलाव

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय दोबारा संभालने के बाद अपने शुरुआती सार्वजनिक वक्तव्यों में से एक में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खासतौर पर कहा कि तेल विपणन क्षेत्र की बड़ी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अथवा बीपीसीएल को बेचने की योजना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीपीसीएल एक अत्यंत सफल महारत्न कंपनी है। महारत्न की श्रेणी में वे सरकारी कंपनियां आती हैं जिनको बहुत अधिक स्वायत्तता हासिल है। पुरी ने कहा कि इस वजह से कंपनी में 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं है।

यह सरकार के रुख में उल्लेखनीय बदलाव है। बीपीसीएल में विनिवेश की योजना 2021 में घोषित की गई थी। यह सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा थी। 2022 में खरीदारों की कमी के चलते इसे वापस ले लिया गया। अब कंपनी बेचने के लिहाज से अत्यधिक मूल्यवान हो गई है। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार तेल कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने के पक्ष में नहीं।

सत्ता में आने वाली हर नई सरकार से कारोबारी समाचार पत्र यही गुहार करते हैं कि वह सरकार के बढ़ते संसाधन अंतर को पाटने के लिए विनिवेश पर ध्यान दे। यह साल भी अलग नहीं था। परंतु नीतिगत लक्ष्य को बदलने की प्रक्रिया ने विनिवेश को दो दशकों से प्रभावित किया है। इससे पता चलता है कि आखिर क्यों 1991-92 से अब तक सरकार केवल पांच बार विनिवेश के लक्ष्य को पार कर सकी है जबकि इसके लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत खासतौर पर एक विभाग तक गठित किया गया था। बीते दशक में सरकार केवल दो बार 2017-18 और 2018-19 में लक्ष्य को पार कर सकी। यह भी पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियों की मदद से आरईसी और एचपीसीएल को खरीदने की बदौलत हुआ।

जिंदगीनामा
कनिका दत्ता

तीन वर्ष पहले विनिवेश को लेकर उम्मीदें में जबरदस्त उछाल थी। 2021-22 के बजट में वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने रणनीतिक विनिवेश को लेकर एक विस्तृत नीति पेश की थी। इसमें रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। इसके तहत सरकार को चार क्षेत्रों में न्यूनतम दखल रखना था। इसमें परमाणु ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, परिवहन, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र शामिल थे।

वास्तव में बीपीसीएल समेत कई कंपनियों को उस वक्त गैर रणनीतिक घोषित किया गया था। इनमें एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस और नीलाचल इस्पात निगम तथा भारतीय जीवन बीमा निगम शामिल थीं।

इनमें से केवल तीन लक्ष्य हासिल हुए। टाटा समूह ने जनवरी और जुलाई 2022 में क्रमशः एयर इंडिया और नीलाचल इस्पात का अधिग्रहण किया और एलआईसी को मई में सूचीबद्ध किया गया। पवन हंस की बिक्री इसलिए टल गई कि पता चला कि उसके लिए सफल बोली लगाने वाली कंपनी कानूनी मामलों में फंसी है। आईडीबीआई बैंक के मामले में नियामकीय मंजूरी, सुरक्षा मंजूरी और मूल्यांकन में अंतर आखिरकार दूर हो गया है। अब सरकार को जरूरत है कि वह विदेशी और भारतीय खरीदारों के बीच चयन करे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश में इसलिए देरी हुई कि इसकी जमीन और अन्य संपत्तियों को लेकर जटिलताएं थीं। अब कैबिनेट महाराष्ट्र सरकार ने स्टांप शुल्क माफी की बात कही है तो इसका विनिवेश नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में है जो सरकार ने चुनाव के पहले पेश किया था।

परंतु अगर बीपीसीएल जैसी मुनाफे वाली कंपनी जिसका इंडियन ऑयल और एचपीसीएल के साथ तेल कारोबार में दबदबा हो वह खरीदार नहीं तलाश पा रही है तो यह समझना मुश्किल है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन को खरीदार कहां से मिले। देश के निर्यात-आयात बाजार में उसकी हिस्सेदारी में भी निरंतर कमी आ रही है। एक ओर जहां इसका विनिवेश किया जा रहा है वहीं सरकार सरकारी तेल, गैस, इस्पात कंपनियों के साथ मिलकर एक नई शिपिंग कंपनी शुरू करने की योजना बना रही है ताकि उनके इस्पातके लिए कच्चा माल आयात किया जा सके। देश के कुल आयात में अकेले तेल की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है, ऐसे में लगता नहीं कि कोई खरीदार ऐसी कंपनी में पैसा लगाएगा जो उसके कारोबार के अहम हिस्से में कटौती करे।

कई कंपनियों का यू पिछड़ना दिखाता है कि मंत्रालय के साथ तालमेल में कमी है। उदाहरण के लिए बीपीसीएल के लाभ-हानि पर नजर डालें तो वह एक सफल कंपनी नजर आती है लेकिन संभावित खरीदार है और बीते ढाई दशक में इन्हें मुक्त करने के तमाम प्रयासों के बावजूद इन सरकार का नियंत्रण है। कंटेनर कॉर्पोरेशन की 30.8 फीसदी हिस्सेदारी बेचने को सरकार ने 2019 में मंजूरी दी थी लेकिन रेलवे की कुछ चिंताओं के बाद यह प्रक्रिया धीमी हो गई।

एक ओर जहां अच्छा प्रदर्शन कर रही कंपनियों को बेचना दिक्कतदेह है तो वहीं बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी भारी भरकम कंपनियां भी बहुत निराश करती हैं जो नाकाम हैं और जिनके 63,000 से अधिक कर्मचारी हैं। सरकार दोनों कंपनियों से कहती आई है कि वे अपनी भूसंपत्तियों का मुद्रीकरण करें लेकिन इस दिशा में बहुत धीमी गति से प्रगति हो रही है। वहीं टाटा समूह जिस तरह एयर इंडिया को बेहतर विमान सेवा बनाने में संघर्ष कर रहा है, यह बात भी संभावित खरीदारों को सरकारी क्षेत्र की मानसिकता से भरे कर्मचारियों वाली कंपनियों को खरीदने के लिए हतोत्साहित करेगी। हकीकत में तमाम खाके तैयार करने के बावजूद सरकार का भी यही नजरिया रहा है।

आपका पक्ष

भारत का बौद्ध विरासत व परंपराओं से अटूट संबंध

अमेरिकी सांसदों की दलाई लामा से मुलाकात पर चीन ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है और इससे जुड़ी कोई भी बात चीन का आंतरिक मामला है। इसमें वह कोई भी बाहरी हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं करेगा। चीन का स्पष्ट इशारा अमेरिका के साथ-साथ भारत की ओर भी है। इसलिए हमें अपनी भावी 'तिब्बत-नीति' पर पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए फूंक-फूंक कर कदम उठाने होंगे। दरअसल, चीन को हमेशा से डर रहा है कि तिब्बत में सबसे अहम माने जाने वाले दलाई लामा और भारत मिलकर चीन में अस्थिरता ला सकते हैं। वैसे चीन केवल तिब्बत मामले में ही आक्रामक नहीं, इससे पहले वह ताइवान और हॉन्गकॉन्ग मुद्दे पर भी भारत और कई बड़े देशों को दूर रहने की नसीहत दे चुका है। तिब्बत की बौद्ध विरासत भारत के साथ उसके ऐतिहासिक संबंधों का सबसे स्पष्ट संकेत है। उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोग इसका अनुसरण करते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर-पश्चिम में लद्दाख तक। तिब्बती बौद्ध धर्म के भविष्य में उनका रणनीतिक महत्त्व और हिस्सेदारी कुछ ऐसी चीज है, जिसे भारतीय नीति निर्माताओं ने हाल में स्वीकार किया है। आज, हम न केवल भारत की बौद्ध विरासत को उजागर करने के लिए एक ठोस और स्पष्ट प्रयास देख रहे हैं, बल्कि इसके भविष्य की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने की इच्छा भी देख रहे हैं। तिब्बत की बौद्ध विरासत के भारत से ऐतिहासिक संबंधों को भारत का पुरजोर तरीके से विश्व पटल पर उठाना समय की मांग है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की थी

वृक्षों को कटने से बचाएं

प्रदूषण और महामारियों जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान पौधरोपण में निहित है। औषधीय पौधों का आयुर्वेद में महत्त्व है जिनसे महामारियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही कई पौधे हमें वृक्ष के रूप में ऑक्सीजन देकर पर्यावरण शुद्ध करते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने पिछले वर्षों के वैश्विक तापमान का मासिक विश्लेषण भी किया। मौसमों में ज्यादा बदलाव अर्थात अधिक गर्मी के करीब पहुंचना चिंतनीय सवाल खड़े करता है। क्या मौसम के निर्धारित माह अपने माह को आगे बढ़ा रहे हैं? अधिक जंगल काटने से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन, अधिक मौसम परिवर्तन और सबको कम संपत्ति ही मिलेगी। ये सर्वविदित है कि वृक्षों से ताप का नियंत्रण और वायुमंडल की विषाक्तता कम होती है। जितने अधिक वृक्ष होंगे, वातावरण उतना ही शुद्ध और स्वच्छ होगा। वृक्षों के होने से वन्य प्राणियों का जीवन सुखद होगा। भविष्य में हरित क्रांति को विलुप्त होने से बचाने हेतु वर्षा ऋतु के समय वृक्षारोपण के पुनीत कार्य में भागीदारी निभाने की सोच विकसित करें। किसी भी निर्माण के पूर्व पेड़ों के ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया अपनाए जाने से वृक्षों को पुनर्जीवन प्राप्त होगा, साथ ही वृक्षों की कटाई भी बंद होगी। वृक्षारोपण नए रोपण में तथा वृक्ष को बड़ा होने का समय बच जाएगा।

संजय वर्मा, धार

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रविवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (एटीआर) में सुबह सात बजकर 10 मिनट पर पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान (आरएलवी) पुष्पक को लगातार तीसरी बार सफलतापूर्वक धरती पर उतारा। इस मिशन में अंतरिक्ष से लौटने वाले यान को तेज हवाओं के बीच उतारने का अभ्यास किया गया, जिससे आरएलवी के विकास के लिए आवश्यक अहम तकनीक हासिल करने में इसरो की विशेषज्ञता बढ़ी है।